



कैद

 subahsaverenews@gmail.com

 facebook.com/subahsaverenews

 www.subahsavere.news

 twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

इस सफ़र में हमसफ़र भी था ; अब याद क्या करना उसे
यानी शहर में एक घर भी था ; अब याद क्या करना उसे

वो हबीब था, वो करीब था, वो धड़कनों – सा अजीज था
वो जरा – सा बेखुबर भी था ; अब याद क्या करना उसे

हँसता न था, रोता न था, उसे ड़ल्लम न था दर्द का
वो जिंदा इस क़दर भी था ; अब याद क्या करना उसे

वो गली गली में फ़िरा किए, बस नाम तेरा लिया किए
कुई गाँव उसका बसर न था ; अब याद क्या करना उसे

वक़्त के सैलाब में, फिर गुम हुआ यूँ ख़्वाब में
वो सुख़्बू था, पैकर न था ; अब याद क्या करना उसे

कुछ अच्छे लोग रहते थे और कहने वाले कहते थे
इस दशत में इक़ शहर था ; अब याद क्या करना उसे ।

- मोहन रमगौरिया

काशी, मथुरा और संभल पर नहीं बन पाई बात

● हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने टुकराया सुप्रीम मध्यस्थता का प्रस्ताव ● दोनों पक्ष सहमत नहीं,कहा-केस लड़कर फैसला चाहते हैं



वाराणसी/मथुरा/संभल (एजेंसी)। यूपी के तीन मंदिर-मस्जिद विवादों को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता का प्रस्ताव टुकरा दिया है। ये विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल की शाही जामा मस्जिद से जुड़े हैं। बार एंड बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समाधान समारोह 2026 पहले के तहत लेटर भेजकर मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था और दोनों पक्षों से सहमति मांगी थी। किसी भी पक्ष ने इसके लिए सहमति नहीं दी। कोर्ट ने यह लेटर कब भेजा था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों ने कहा है कि वे अदालत में ही केस लड़कर फैसला चाहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट परिसर में 21 से 23 अगस्त तक समाधान समारोह के तहत विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लंबी कानूनी लड़ाई के बजाय बातचीत के जरिए हल निकालना है।

प्रसंगवश

ले.जन. एच.एस. पनाग (रि.)

भारतीय सेना ने आजादी के बाद अपने सबसे महत्वाकांक्षी संरचनात्मक तथा संगठनात्मक सुधार को लागू करते हुए अभी 1 जुलाई को अपने 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स' (IBG) (एकीकृत युद्ध समूहों) को प्रस्तुत किया। लेकिन इसके साथ एक असुविधाजनक सवाल भी उभरा: भावी युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही सेना के लिए जिस सुधार की जरूरत 2002 में ही मान्य की जा चुकी थी और जिसकी संकल्पना 2018 में ही तय की जा चुकी थी उस सुधार को लागू करने में क्या 10 साल और लगाए जा सकते हैं?

बहरहाल, सुधार को संकल्पना पत्र से निश्चित ही आगे बढ़ाया जा चुका है। इसके पहले चरण में अगले दो साल में, XVII माउटेन स्ट्राइक कोर के दो डिवीजनों को पांच IBG और एक फायर सपोर्ट ग्रुप (कोर के स्तर पर) में बदल दिया जाएगा। सुधरे हुए मॉडल को सेना की 42 इन्फैन्ट्री, माउंटेन, रैपिड, आर्माईड, और आर्टिलरी डिवीजनों, और 12 आर्मर्ड/ इन्फैन्ट्री ब्रिगेडों पर लागू किया जाएगा।

लेकिन, IBG का गठन पुनर्गठन की लंबी प्रक्रिया में नहीं तब्दील होनी चाहिए। यह भारतीय सेना के भावी रणक्षेत्र की तकनीकी धुरी बननी चाहिए। और यह काम अगले पांच वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए।

IBG की जड़ें ऑपरेशन संबंधी बुनियादी समस्या में पाई जाती हैं। दो सदियों से, पारंपरिक कंबाईंड-आर्म्स डिवीजन ही सेनाओं के युद्ध लड़ने वाले पूर्वनिर्धारित समूह रहे हैं। इनमें सैनिकों की बड़ी संख्या की, हेडक्वार्टर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, और ये अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ते हैं। ये लंबे समय तक चलने वाले अभियान के लिए तैनात किया जाता है, जबकि भावी युद्ध में समय की कमी पड़ने वाली है।

ऑपरेशनों के लिए डिवीजनों के संसाधनों से ही तैयार किए जाने वाले ब्रिगेड बैटल ग्रुप्स में संगठनात्मक एकजुटता का अभाव होता है।

भारतीय सेना ने यह सबक 2001-02 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान काफी कष्ट से सीखा, जब उसने सक्रिय होने में तीन सप्ताह लगा दिए थे और पाकिस्तान के खिलाफ पहल करने का मौका और बढ़त गंवा दी थी। इसके बाद 2003-04 से, सेना ने डिवीजन के आकार के बैटल ग्रुप्स के बने काम करना शुरू कर दिया। इन्हें युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशन की आक्रामक, 'कोल्ड स्टार्ट' रणनीति को लागू करने के लिए उतारने की योजना थी।

लेकिन इन बैटल ग्रुप्स का आकार भी काफी बड़ा था और इन्हें धीरे-धीरे ही सक्रिय किया जा सकता था। 2018 में, जनरल बिपिन रावत ने चुनौती का सीधा सामना किया और उभरते IBG का विस्तृत अध्ययन करने का आदेश दिया। 2019 में, मैदानी इलाके में 9 कोर में और पहाड़ी इलाके में 17 कोर में IBG के साथ प्रयोगात्मक फील्ड अभ्यास किए गए ताकि संकल्पना का परीक्षण हो और उसमें सुधार किया जाए।

IBG के गठन में तेजी लाने का एक कारण यह भी है कि भारत और इसके प्रतिद्वंद्वी चीन और पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस हैं, जिसकी वजह से पूर्ण पैमाने वाले निर्णायक पारंपरिक युद्ध की संभावना खत्म हो गई है। भविष्य के युद्ध सीमित समय और स्थान में लड़े जाएंगे; उनमें सटीक मार करने वाले घातक सैन्य टेक्नोलॉजी और तेज कार्रवाई का बोलबाला रहेगा। इस मामले में ऑपरेशन सिंदूर सटीक उदाहरण है। ऐसी लड़ाई में, विवादित सीमा पर जमीन पर कब्जा करने के लिए अग्रिम ऑपरेशन किए जाने की ज्यादा संभावना रहेगी। ऐसे खतरे पैदा करने या उनका मुकाबला करने के लिए बहुत तेज कार्रवाई करने वाले समूहों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चुनौती उसे लागू करने की है।

आशुतोष भैया के लिए प्राण झोंक दिए जाएंगे

‘एक-एक दरवाजे पर जाऊंगा...’, भाषण देते समय रोने लगे नरोत्तम मिश्रा; फिर सीएम ने संभाला

दतिया उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भरा नामांकन



जनसभा में एक ऐसा भावुक पल आया, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

दतिया के किला चौक पर आयोजित भाजपा की सभा में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा में फूट की बातें कर रही है, लेकिन पार्टी पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरी है और कार्यकर्ताओं के दम पर जीत दर्ज करेगी।

अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा कि दोनों की राजनीति में स्पष्ट अंतर है।

दतिया उपचुनाव- भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी

दतिया विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा के प्रस्तावित स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई है। 11 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी गई सूची सोमवार सुबह सामने आई है। इस सूची में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों से लेकर संगठन के बड़े चेहरों को शामिल किया गया है। इस सूची में पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। सूची के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा खुद प्रचार की अगुवाई कर रहे हैं।



16 जुलाई से यही जमाऊंगा डेरा- नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं 16 जुलाई से यहीं पर डेरा जमाऊंगा। मैं क्षेत्र में एक-एक दरवाजे पर जाकर अपना शीश नवाऊंगा। मैं एक-एक गांव के अंदर जाऊंगा। यह कहते हुए नरोत्तम मिश्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पास खड़े आशुतोष तिवारी के कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया।

भावुक होकर कहा कि मैं आशुतोष को जिताऊंगा- आशुतोष तिवारी को आशीर्वाद देते हुए नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैं आशुतोष को जिताऊंगा। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर दतिया की जनता का अभिवादन किया और मंच की ओर चले गए।

कांग्रेस पर किया हमला- सीएम मोहन यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र की बात है तो अलग-अलग कानून क्यों होने चाहिए। पूरे देश में एक सामान कानून की बात होनी चाहिए। कांग्रेसी इससे मुंह छुपा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता की पार्टी है, यह राजा-महाराजाओं की पार्टी नहीं है।

खामेनेई की मौत से गुस्साए ईरान की ‘हिट लिस्ट’ में ट्रंप

नेतन्याहू और स्टार्मर सहित 13 नेताओं के और नाम हैं शामिल

तेहरान (एजेंसी)। अमेरिका-ईरान की जंग के बीच एक और घटनाक्रम इस समय चर्चा का विषय बन गया है। ईरान के एक अखबार ने सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या का बदला लेने के लिए टारगेट किए जाने वाले लोगों की एक लिस्ट छपी है। इस लिस्ट में अमेरिका,



इजरायल और यूरोपियन देशों के नेता शामिल हैं। इस अखबार में एक पोस्टर छपा गया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य बड़े नेताओं की तस्वीरें दिखाई गई हैं। यह लिस्ट ईरान की राजधानी में अधिकारियों द्वारा पब्लिश किए जाने वाले हमशहरी अखबार में छपी गई है। इस ग्राफिक के साथ अखबार ने हेडलाइन दी- अचानक मौत के लिए तैयार रहें। साथ ही मोजान्बा खामेनेई का बयान भी छपा गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बदला हमारे देश की इच्छा है और इसे जरूर पूरा किया जाना चाहिए।

जो पारंपरिक तोपों की रेंज से आगे तक मार कर सकेगी, और यह सब उसका अपना होगा या एफएसजी से हासिल होगा। फायर करने की व्यवस्था तत्काल सक्रिय होने वाले सेंसर नेटवर्क से जुड़ी होगी। भावी युद्धक्षेत्र इस बात से परिभाषित होगा कि जो नजर में आ रहा है उसे पहचाना जाए और मिनटों में खत्म किया जाए।

चौथी विशेषता: कमांड और कंट्रोल सिस्टम एआई-सक्षम युद्धक्षेत्र प्रबंधन और ऐसे निर्णय व्यवस्था का इस्तेमाल करे जो उपग्रहों, ड्रोनों, रडारों, और जमीनी सेंसरों से हासिल डाटा को मिलाकर ऑपरेशन की एक साझा तस्वीर तैयार करे।

पांचवीं विशेषता: साजोसामान को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया जाए जिसके साथ भविष्य के लिए रखरखाव, स्वायत्त आपूर्ति, गोला-बारूद के अलग-अलग भंडार, और डिजिटल इनवेंटरी के प्रबंधन की व्यवस्था शामिल हो।

उपरोक्त क्षमताओं के बिना गठित IBG छोटे डिवीजन से थोड़े ही बेहतर होंगे। भारत ब्रिगेड-केंद्रित मॉडल को अमेरिकी सेना द्वारा इसे अपनाए जाने के करीब दो दशक बाद और चीनी सेना पीएलए के एक दशक बाद लागू कर रहा है। इसलिए चुनौती उनके ढांचे की नकल करने की नहीं बल्कि सीधे छलांग लगाकर ड्रोन-समर्थित नेटवर्क से जुड़ी युद्ध प्रणाली को अपनाने की है। चीन ने सेना में जो सुधार किए हैं, वे शायद ज्यादा प्रासंगिक हैं। मेरी सबसे बड़ी चिंता सुधारों की सुस्त गति को लेकर है। XVII कोर के दो डिवीजन को अगर पांच IBG और एक एफएसजी में बदलने में दो साल लगते हैं, तो इस मॉडल को बाकी सेना पर लागू करने में दस साल और लगेंगे। भारत के लिए जो रणनीतिक माहौल है उसमें यह समयसीमा कारगर नहीं होगी।

(द प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

प्रदेश से कहां गया मानसून? एकदम से थम गई बारिश

● 15-17 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना

भोपाल (नप्र)। एमपी में दक्षिण-पश्चिम मानसून की रफ्तार पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, राज्य में मानसून को ऊर्जा देने वाली मौसम प्रणालियां कमजोर पड़ने से बारिश का दौर थम सा गया है। हालांकि, किसानों और आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी में एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने जा रहा है, जिससे जुलाई के दूसरे पखवाड़े में प्रदेश भर में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू होने की जोरदार संभावना है।

पूर्व मौसम वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश के किसी भी हिस्से में भारी या अति भारी बारिश दर्ज नहीं की गई है। अगले दो से तीन दिन प्रदेश में बारिश को लेकर कोई बड़ा अपडेट या अलर्ट भी नहीं है। हालांकि 15 जून से मौसमी परिस्थितियां बदलेंगी और एक बार फिर जोरदार बारिश का सिस्टम बनने की संभावना है।

पूर्वी एमपी में हल्की फुहारें

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां केवल पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही सिमटी रहीं। मऊगंज के हनुमान में 16 मिमी, नेगढ़ी में 4 मिमी, सीधी के सिहवल्ल में 3 मिमी, गोपदबनास में 1.2 मिमी और अनुपपुर के बिजुरी में 1.1 मिमी पानी गिरा। वहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम साफ रहा और कहीं भी उल्लेखनीय बारिश दर्ज नहीं की गई। गरज-चमक की स्थिति कमजोर रहने के कारण भिंड में हवा की अधिकतम रफ्तार 35 किमी प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई।

शताब्दी में एक्सपायरी ब्रेड परोसने पर आईआरसीटीसी का बड़ा एक्शन

वेंडर पर 1 लाख जुर्माना, लापरवाही बरतने पर मैनेजर समेत स्टाफ को हटाया

भोपाल (नप्र)। नई दिल्ली से रानी कमलापति (भोपाल) आ रही 12002 शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रियों को एक्सपायरी डेट वाली ब्रेड परोसे जाने के मामले में आईआरसीटीसी ने बड़ी कार्रवाई की है। केंटरिंग वेंडर पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जबकि मामले में लापरवाही सामने आने पर मैनेजर सहित संबंधित स्टाफ को हटा दिया गया है।

वेंडर पर 1 लाख की पेनल्टी

मीडिया को विवेक रावत ने बताया कि एक्सपायरी ब्रेड परोसने के मामले को गंभीरता से लिया गया है। संबंधित केंटरिंग वेंडर पर एक लाख रुपए की आर्थिक पेनल्टी लगाई गई है। साथ ही, जिस स्टाफ की जिम्मेदारी थी, उसे तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं।



बहुरेंगे भीगने वाले दिन जमकर बरसेंगे बदरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान, गुजरात और उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बीते 3-4 दिनों में कमजोर

- 7 दिन में कई राज्यों में फिर रफतार पकड़ेगा मानसून
- अग्नी राजस्थान-गुजरात समेत कई राज्यों में कमजोर
- यूपी-बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट

पड़ा मानसून 20 जुलाई से फिर रफतार पकड़ेगा। सैटेलाइट इमेज में पूर्वी, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर घने बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, बांग्लादेश और



पूर्वोत्तर के ऊपर बने चक्रवाती सिस्टम और पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के कारण अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां तेज होंगी। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 6-7 दिनों तक कई जगह अच्छी से भारी बारिश होने का अनुमान है।

- उत्तराखंड में लैंडस्लाइड से 126 सड़कें बंद- उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। 2 नेशनल हाईवे समेत 126 सड़कें बंद हैं। स्थानाचटटी के पास ऋषिकेश-यमुनोत्री हाईवे रविवार को लगातार तीसरे दिन भी बंद रहा। हरियाणा में हिमाचल से आ रहे पानी के कारण यमुना और मारकंडा नदी में पानी बढ़ गया है। इससे कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। दिल्ली में बारिश से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। रविवार को यमुना नदी में नहाने गए 4 बच्चे तेज बहाव में बह गए।
- राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून- राजस्थान में मानसून का पहला दौर थमने के बाद अब बारिश की रफतार धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले करीब एक हफ्ते तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना कम है। जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश इलाकों में मौसम ड्राई रहेगा। हालांकि, 14 और 15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरु और आसपास के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भी अगले 5-6 दिनों तक मौसम साफ रहेगा।

संक्षिप्त समाचार

नागरिकता का फैसला निष्पक्ष प्रक्रिया से हो सुप्रीम फैसला,असम में विदेशी घोषित 27 लोगों को राहत

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने से जुड़े मामलों में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि नागरिकता और विदेशी होने का सवाल सविधान और कानून से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण विषय है। सभी मामले दोबारा सुनवाई के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को भेज दिए गए हैं। इन लोगों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया था। उन्होंने इस फैसले को गुवाहाटी हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद सभी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

ई 20 पेट्रोल से खराब हो रही गाड़ियों पर सरकार सख्त राज्यों को दिया मिलावटखोरों पर कड़ा ऐवशन लेने का निर्देश

नई दिल्ली (एजेंसी)। ई 20 पेट्रोल इस समय देश में सबसे चर्चित मुद्दों में से एक बना हुआ है। सरकार इसको देशभर में लागू कर चुकी है। हालांकि, लोग शिकायत कर रहे हैं कि इससे उनकी गाड़ियों में खराबी आ रही है, इंजन खराब हो रहा है और माइलेज कम हो रहा है। लोगों में ई 20 पेट्रोल की क्वालिटी और इंजन सुरक्षा को लेकर काफी चिंताएं देखी जा रही हैं। इस सबके बीच मोदी सरकार काफ़ी सख्त है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पेट्रोल में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मिलावटखोरों से कड़ाई से निपटने का आदेश- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में एक नोट जारी किया था। मंत्रालय ने निर्देश जारी कर सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा है कि ईंधन के रखरखाव या सफाई चैन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

डीएमके को दुश्मन कहने वाले विजय से दोस्ती संभव नहीं

चेन्नई (एजेंसी)। थलपति विजय की पार्टी टीवीके अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो डीएमके विपक्षी दलों के गुट से बाहर हो जाएगा। डीएमके चीफ एम के स्टालिन ने बीजेपी विरोध के नाम पर सीएम विजय से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। डीएमके सांसद गणपति पी. राजकुमार ने कांग्रेस



पर भी पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया। डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि सीएम विजय बार-बार डीएमके को अपना दुश्मन बता चुके हैं, ऐसे में हम उनके साथ इंडिया गठबंधन में साथ कैसे हो सकते हैं। पार्टी ने साफ किया कि बीजेपी के विरोध के नाम पर तमिलनाडु में केरल और पश्चिम बंगाल वाला मौडल नहीं चलेगा। यहां तो डीएमके वाला ही मौडल चलेगा।

हाय महंगाई, तू कहां से आई

- 17 महीनों में पहली बार आरबीआई के टारगेट से ऊपर
- जून में महंगाई ने पकड़ी रफतार, बढ़कर 4.38 फीसदी हुई

नई दिल्ली (एजेंसी)। जून में भारत की खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.38 फीसदी हो गई। इसकी वजह खाने-पीने की चीजों और ईंधन की ऊंची कीमतें, पश्चिम एशिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन और मॉनसून के असमान रहने की चिंताएं थीं। इनसे कीमतों पर दबाव बना रहा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ताजा आंकड़ा 17 महीनों में पहली बार भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 4 फीसदी के मीडियम-टर्म इनफ्लेशन टारगेट से ऊपर चला गया। इससे कम महंगाई का लंबा दौर खत्म हो गया। सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के जारी आंकड़ों से पता चला कि रिटेल इनफ्लेशन रेट मई के 3.93 से बढ़कर जून में 4.38 फीसदी हो गई। यह मोटे तौर पर बाजार की उम्मीदों के मुताबिक थी।



- अर्थशास्त्रियों ने दी चेतावनी- अर्थशास्त्रियों ने यह भी चेतावनी दी कि ग्लोबल एनर्जी कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से भारत का कर्कर अकाउंट डेफिसिट बढ़ सकता है। रुपये के कमजोर होने की संभावना है। इंपोर्टेड महंगाई बढ़ सकती है। जबकि अनियमित मॉनसून के कारण साल के बाकी समय में खाने-पीने की चीजों की कीमतें ऊंची बनी रह सकती हैं।

मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में नहीं हुआ कोई बदलाव

महंगाई दर का यह आंकड़ा भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जून की मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा में बेंचमार्क रेपो रेट को 5.25 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने और अपने न्यूट्रल पॉलिसी रुख को बनाए रखने के कुछ हफ्तों बाद आया है। कारण है कि नीति-निर्माताओं ने महंगाई के जोखिमों और आर्थिक विकास को सहारा देने की जरूरत के बीच संतुलन बनाया था। सेंट्रल बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अपने महंगाई दर के अनुमान को भी अप्रैल में लगाए गए 4.6 से बढ़ाकर 5.1 फीसदी कर दिया था। इसका कारण चीजों की कीमतों का लगातार बढ़ना है।

मैं बिहार आकर अपना सुदर्शन चक्र चलाऊंगा

- वीणा मानवी को हिरासत में लेने पर भड़के तेज प्रताप



पटना (एजेंसी)। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव में हर दिन एक नया और चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिल रहा है। चुनावी सरगमियों के बीच, तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार वीणा मानवी को नामांकन प्रक्रिया पूरी करते ही पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर से हिरासत में ले लिया। इस हार्ड-प्रोफाइल ऐक्शन के बाद बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। फिलहाल दिल्ली में मौजूद पार्टी संरक्षक तेज प्रताप यादव ने इस पूरी कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी प्रत्याशी को जानबूझकर एक झूठे मामले में फंसाकर चुनाव प्रक्रिया से दूर करने की साजिश रची जा रही है। नॉमिनेशन करते ही वीणा को पुलिस ने दबोचा- अब तेज प्रताप यादव की पार्टी से चुनावी मैदान में उतरी वीणा मानवी को नामांकन के तुरंत बाद हिरासत में ले लिया गया है।

महाकाल-हरसिद्धि मार्ग का नामकरण पं. सूर्यनारायण त्यास के नाम पर होगा

उज्जैन। ज्योतिर्विद्या के प्रख्यात पंडित पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जिन्होंने आजादी के बाद उज्जैन को विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम कीर्ति मंदिर जैसी सौगातें दी और अखिल भारतीय कालिदास समारोह का आरम्भ वर्ष 1928 से किया और बाद में सिंधिया शोध प्रतिष्ठान, कालिदास अकादमी जैसी सांस्कृतिक संस्थायें स्थापित की अब प्रशासन महाकाल से हरसिद्धि मार्ग का नामकरण पंडित सूर्यनारायण व्यास के नाम से करने जा रहा उल्लेखनीय है कि आगामी सिंहस्थ को देखते हुए शहर में विकास और चौड़ीकरण के बड़े कार्य चल रहे हैं, इसी सिलसिले में श्रीमहाकालेश्वर मन्दिर के समीप स्थित भारती भवन के सामने की कुछ जमीन , पंडित पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास के सुपुत्र राजशेखर व्यास ने प्रशासन को निशुल्क प्रदान करने की सहमति दी है। अखिल भारतीय कालिदास परिषद के अध्यक्ष श्री राजशेखर व्यास ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्रदेश सरकार की शहर के विकास की योजनाओं में सभी सहयोग कर रहे हैं और भारती भवन के हिस्से की जमीन, सड़क चौड़ीकरण के लिए निःशुल्क प्रदान कर हम भी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। पंडित जी भी शहर के विकास के लिए कृतसंकल्पित रहे और महाकाल के इस महान भक्त ने महाकाल में शंख द्वार, चाँदी द्वार, मोजेक टाइल्स भी लगवायी,क्षिप्रा द्वार बनाया,बोहरा वार्ड बच्चों का अस्पताल बनवाया और आधुनिक उज्जयिनी का जो रूप हैं वह पद्मभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास की देन है।

कुख्यात वन्यजीव शिकारी अजीत पारधी की जमानत निरस्त

● मध्यप्रदेश लाया जाएगा आरोपी, वंदपुर महाराष्ट्र में थायिक हिरासत में है निरुद्ध भोपाल (न्र)। मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को वन्यजीव अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई में बड़ी सफलता मिली है। पंच टाइगर रिजर्व में वर्ष 2013 में दर्ज वन्यजीव शिकार प्रकरण के कुख्यात आरोपी अजीत पारधी की जमानत विशेष न्यायालय, जबलपुर ने निरस्त कर दी है। न्यायालय अब आरोपी की पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करेगा, जिसके बाद उसे महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश लाया जाएगा। वन्यजीव अपराधों से जुड़े मामलों में यह प्रदेश का एक विरला मामला है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएफ), 2023 की धारा 480 के तहत जांच एजेंसी के आवेदन पर पहले से जमानत प्राप्त आरोपी की जमानत और बंधपत्र निरस्त किए गए हैं। विशेष न्यायालय, जबलपुर से सशर्त जमानत मिलने के बाद भी एसटीएसएफ उसकी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखे हुए थी।

गो हत्या बैन के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

कहा- इसमें सुधार की जरूरत,मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था-ये इस्लाम में जरूरी प्रथा नहीं

हाईकोर्ट ने सविधान के अनुच्छेद 48 का हवाला दिया था

हाईकोर्ट ने कहा था कि सविधान का अनुच्छेद 48 राज्य सरकार को गाय, बछड़ों और दुधारु-पशुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। कोर्ट ने तमिलनाडु एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट, 1958 की धारा-4 का उल्लेख किया। इसमें कहा गया है कि 10 साल से ज्यादा उम्र और प्रजनन के अयोग्य पशु को भी प्रमाणपत्र मिलने के बाद काट जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस प्रावधान की सख्ती से व्याख्या होनी चाहिए।

इसे कायम नहीं रखा जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने आज इस मामले में नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी।

मद्रास हाईकोर्ट ने कुर्बानी रोकने को कहा था- मद्रास हाईकोर्ट ने 27 मई को (बकरीद से एक दिन पहले) तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य में बकरीद या किसी अन्य दिन गाय और बछड़ों की कुर्बानी न हो। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायण की बेंच ने कहा-सविधान सभा की बहस में कहा गया था कि गाय भारत में पूजनीय मानी जाती है। भगवान कृष्ण के समय से हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है।



कई मुस्लिम शासकों ने भी गोहत्या पर रोक लगाई थी। महात्मा गांधी भी गो संरक्षण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था-बकरीद पर गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं- 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की पशु वध संबंधी गाइडलाइन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या

बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने कहा, खुले सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी पशु का वध पूरी तरह बैन है। इंद-उल-जुह में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। पूर्व तुणमूल नेता व विधायक हुमायूं कबीर ने गाइडलाइन का विरोध करते हुए इंद पर हर हाल में कुर्बानी की धमकी दी है।

देश के लिए 3 जंग लड़ने वाले पूर्व सैनिक से धोखाधड़ी!

90 साल की उम्र में चुन्नीलाल अपनी ही जमीन के लिए कर रहे संघर्ष

जैसलमेर (एजेंसी)। जिस योद्धा ने 1962 में चीन और 1965 व 1971 में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए, वह आज अपनी ही जमीन को बचाने के लिए 90 साल की उम्र में लाठी टेकते हुए दफतरो के चक्कर काट रहा है। 1962, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों के गवाह रहे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा निवासी कैप्टन चुन्नीलाल के साथ जैसलमेर में



- एसपी के दखल के बाद जागा सिरस्ट- हेरानी की बात यह है कि देश के इस जांबाज के बेटे मुल्तान सिंह ठाकुर को फर्जीवाड़ा पकड़ने के बाद भी एफआईआर दर्ज कराने के लिए थानों की खाक छाननी पड़ी। जब मामला जैसलमेर एसपी के पास पहुंचा, तब जाकर कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे सिंडिकेट को खंगाल रही है कि आखिर कौनसे कौटूट्यों में बंद सरकारी डेटा इन भू-माफियाओं तक कैसे लीक हो रहा है। देश की रक्षा करने वाले एक वयोवृद्ध सैनिक के साथ हुआ यह कृत्य अब स्थानीय जनता और पूर्व सैनिकों के बीच भारी आक्रोश का कारण बन चुका है।

पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑटिज्म और बौद्धिक अक्षमता पर कार्यक्रम

भोपाल । सत्यमेव मानसिक विकास केंद्र की निदेशिका रिमता कुमारी द्वारा आंगनवाड़ी क्रमांक 1146, गोविंदपुरा में बाल, महिला एवं एलजीबीटीक्यू के मानसिक समस्या को समझने के लिए पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ऑटिज्म और बौद्धिक अक्षमता की पहचान एवं पुनर्वास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम की शुरुआत पोस्टपार्टम डिप्रेशन की पहचान के साथ की गई । आंगनवाड़ी से गर्भवती एवं प्रसूति महिलाएँ जुड़ी रहती है, इसलिए उनके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर इस



कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में दो महिलाओं ने सार्वजनिक तौर पर इससे जुड़ी अपनी व्यक्तिगत अनुभव साझा किया जो इससे गुजरि थीं । इसके बाद बौद्धिक अक्षमता और ऑटिज्म वाले बच्चे की शीघ्र पहचान एवं शीघ्र हस्तक्षेप से बेहतर पुनर्वास तक की आधारभूत जानकारी दी गई, ताकि लोग जागरूकता से ऐसे बच्चों की पहचान कर उचित समय पर बिना लापरवाही थरेपी से जोड़ सकें । आंगनवाड़ी सहायिका निशा यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम से मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगता सम्बंधित जानकारी मिल रही है, इससे उन्हें यह फायदा हुआ है कि अब वह इस तरह की महिलाएँ और बच्चों के लिए उनके आंगनवाड़ी से जुड़े लोगों को उचित जानकारी दे पाएंगी ।प्रतिभागियों और आंगनवाड़ी सहायिका ने बताया कि इससे पहले उनके केंद्र में मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं हुई है । इस कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य पर और लिंग आधारित भेदभाव पर कई सवाल-जवाब हुए, इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी की सहायिका और लगभग 28 महिलाएँ एवं बच्चे शामिल हुए ।

कैदियों को कोर्ट तक लाने में अपनी जेब से खर्च करते हैं पुलिसवाले

जबलपुर (नप्र) । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों द्वारा कैदियों को कोर्ट ले जाने के दौरान होने वाले खर्च को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है । कोर्ट ने जेल महानिदेशक को नोटिस जारी कर



मंगलवार तक यह बताने को कहा है कि क्या अदालतों में कैदियों को ले जाने वाले पुलिसकर्मियों को उनके रहने और खाने पर खर्च होने वाले पैसे का रीडर्समेंट मिलता है या नहीं । यह मामला रीवा के दहेज उत्पीड़न और हत्या के दोषी अब्दुल माजिद की अपील पर सुनवाई के दौरान सामने आया । माजिद को रीवा से 250 किलोमीटर दूर जबलपुर हाईकोर्ट लाया गया था ।

सुनवाई के दौरान जजों के सामने खुली पोल

जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए. के. सिंह की बेंच ने कैदी माजिद को लेकर आए एएसआई हरीलाल वर्मा और हेड कांस्टेबल महेश वर्मा से पूछा कि क्या कैदी ने खाना खाया और क्या उन्हें कैदियों को खाना खिलाने के लिए कोई अलग से फंड या आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च मिलता है ? पुलिसकर्मियों के जवाब ने जजों को हैरान कर दिया । उन्होंने बताया कि कैदियों के ठहरने और खाने-पीने पर खर्च होने वाले पैसे की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है । उन्हें यह पूरा खर्च अपने खुद के दैनिक भत्ते से उठाना पड़ता है । कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है ।

धनंजय वर्मा स्मृति आलोचना सम्मान प्रो. अरविंदाक्षन का समारोह आज

भोपाल । आचार्य धनञ्जय वर्मा सृजन पीठ, भोपाल द्वारा भारतीय एवं पाश्चात्य आलोचना के समन्वयक, रचना के सहयात्री आलोचक धनञ्जय वर्मा की स्मृति में वर्ष 2026 के सम्मान से केरल के हिन्दी और मलयाली भाषा के वरिष्ठ कवि, आलोचक प्र. ए. अरविंदाक्षन को सम्मानित किया जाएगा । सम्मान समारोह 14 जुलाई को शाम 5 बजे मायाराम सुरजन भवन ,शास्त्री नगर भोपाल में आयोजित होगा ।सम्मान स्वरूप रु. 21 हजार की राशि, शॉल, शीफल और प्रशस्ति पत्र के साथ उन्हें भेंट की जाएगी । यह जानकारी कार्यक्रम संयोजक निवेदिता वर्मा ने दी ।

भोपाल में रिवाॅल्वर छीनकर किसान को मारी गोली

पैर को चीरते निकली बुलेट; थार हटाने के लिए हॉर्न बजाने पर भड़के 3 युवक

भोपाल (नप्र)। भोपाल के मिसरोद इलाके में किसान को गोली मारने का सीसीटीवी सामने आया है। वीडियो में तीन युवक पहले किसान से मारपीट करते हैं, फिर उसकी लाइसेंस रिवॉल्वर छीनकर दो फायर कर देते हैं। एक गोली किसान के पैर को चीरते हुए निकल जाती है, जबकि दूसरी मिस हो जाती है। घटना शनिवार देर रात सागर रॉयल होम्स की है। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

किसान को गोली और रायसेन में तालिबानी प्रताड़ना, उमंग सिंघार ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा- मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गरमा गई है। प्रदेश



टेक हब बन रहा है एमपी, स्पेन की कंपनी स्थापित कर रही डेटा सेंटर 40,000 करोड़ रुपए का आया निवेश: सीएम

भोपाल (नप्र)। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया है। इस कॉन्क्लेव का मकसद डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर कहा कि एमपी टेक सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने 20 औद्योगिक इकाइयों का भी लोकार्पण किया है। समारोह में इंडिया लीड फॉर ग्लोबल प्ले और एमपीएसईडीसी के बीच महत्वपूर्ण एमओयू भी साइन किया गया।

- **टेक में भी आगे बढ़ा रहा है एमपी-** सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की पहचान भी पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग और फॉरेस्ट थी, लेकिन अब डिफेंस से लेकर ड्रोन, साइंस टेक से लेकर रिन्युएबल एनर्जी, इंडस्ट्री कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर गोइंग सेक्टर तक एमपी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ग्रोथ कॉन्क्लेव तीसरे संस्करण तक पहुंच गया है। पिछले दो वर्षों में हमने जो संकल्प लिए, उन्हें पूरा किया। दो संस्करणों में हमें 46 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, 22 नए औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण हुआ और 4 नई परियोजनाओं का भूमि-पूजन किया गया।
- **12 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश धरातल पर उतरे-** उन्होंने कहा कि ग्लोबल इवेस्टर्स मीट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12 हजार करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इससे हमारी काम करने की गति और आत्मविश्वास झलकता है। मोहन यादव ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से भी भोपाल पहचाना जाता है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिया था। इसी तरह हमारे



- **स्पेन की कंपनी स्थापित कर रही डेटा सेंटर-** मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों

ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के माध्यम से अब तक 28 हजार 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। बार्सिलोना (स्पेन) के सबमर ग्रुप ने अपने संकल्प को दोहराया है और 1 गीगा बाइट के डेटा सेंटर

जिला अस्पतालों के उन्नयन एवं पद स्वीकृति की कार्यवाही प्राथमिकता से करें पूर्ण: उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

विशेषज्ञों की भी पदोन्नति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय कार्यों में तेजी लाते हुए सभी लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जिला अस्पतालों के उन्नयन तथा नवीन पदों के सृजन एवं स्वीकृति से संबंधित विभागीय कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक प्रभाव एवं बेहतर हो सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि नर्सिंग भर्ती परीक्षाओं का समयबद्ध आयोजन किया जाए तथा पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि



बांडधारी चिकित्सकों के पोस्टिंग आदेश शीघ्र जारी कर चिन्हित चिकित्सकों की समय पर पदस्थापना एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विशेषज्ञ चिकित्सकों

सहित अन्य चिकित्सकों की पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए इसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, श्री अशोक बर्णवाल उपस्थित थे।

पहली ही बारिश में बह गया सिंगरौली का नया चेक डैम

कलेक्टर का बड़ा एक्शन, सचिव सरपेंड, सब-इंजीनियर की छुटी तय

सिंगरौली (नप्र)। जिले से भ्रष्टाचार और घंटिया निर्माण का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां के देवसर जनपद पंचायत के अंतर्गत कठदहा गांव में घघिया नाले पर बना एक नया चेक डैम सीजन की पहली ही बारिश में ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हैरानी की बात यह है कि इस चेक डैम का निर्माण महज दो हफ्ते पहले ही पूरा हुआ था। बांध के टूटते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। सिंगरौली कलेक्टर गौरव बेनल ने तुरंत इस मामले में तकनीकी जांच के आदेश दिए, जिसमें निर्माण कार्य को लेकर कई चौकाने वाले खुलासे हुए हैं।

बिना लोहे के खड़ा कर दिया ग्रेविटी डैम- तकनीकी जांच रिपोर्ट में सामने आया कि चेक डैम के निर्माण में तय नियमों और पैमानों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। नियमों के मुताबिक बांध की नींव कम से कम 1 मीटर गहरी होनी चाहिए थी, लेकिन ठेकेदार और जिम्मेदारों ने इसे बेहद उथला रखा। सबसे गंभीर बात यह रही कि ग्रेविटी डैम के डिजाइन में किसी भी तरह के लोहे का इस्तेमाल ही नहीं किया गया, जिससे पहली ही बारिश के पानी का



दबाव बांध झेल नहीं सका। इसके अलावा, सब-इंजीनियर ने बिना किसी फाइनल मेजरमेंट और मूल्यांकन के ही काम को पास कर दिया। इसके बाद ग्राम पंचायत ने बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के ही प्रोजेक्ट के पैसे भी निकाल लिए।

कलेक्टर का बड़ा एक्शन- खामियां उजागर-

नींव 1 मीटर से कम खोदी गई, लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ और डाउनस्ट्रीम स्लोप भी मानकों के विपरीत था।

पैसे की निकासी- बिना काम के मूल्यांकन के ही ग्राम पंचायत ने 15वें वित्त आयोग के फंड से करीब 4 लाख रुपये निकाल लिए।

पुलिस विभाग में सबेदार और कार्यवाहक आरआई के प्रमोशन

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के पुलिस विभाग में प्रदेश के 168 सबेदार और कार्यवाहक रक्षित निरीक्षकों को रक्षित निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है। पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा आदेश जारी होने के बाद पुलिस महकमे में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है।

जीएडी के पत्र के बाद शुरू हुई प्रमोशन प्रक्रिया- बता दें कि 30 जून 2026 को मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र और मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के विधिक परामर्श के अंतर्गत यह प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस आदेश के तहत प्रमोट हुए अधिकारियों को रक्षित निरीक्षक के रिक्त पदों पर आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है। इन सभी अधिकारियों को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के तहत पे-मेट्रिक्स लेवल-10 (वेतनमान 9300-34800 + 4200) का लाभ कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से मिलेगा। विभागीय जांच या अथुरी ट्रेनिंग वाले अफसर नहीं होंगे रिलीव



संपादकीय

त्रिपक्षीय समझौता : नुकसान में नफ़ा!

सरदार सरोवर परियोजना मामले में केन्द्र सरकार की मध्यस्थता से हुए त्रिपक्षीय समझौते को लेकर मध्यप्रदेश सरकार जो स्पष्टीकरण दे रही है, जो किसी के गले नहीं उतर रही है। जो बातें सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि राज्य सरकार ने केन्द्र की मोदी सरकार के दबाव में ऐसे समझौते पर हामी भर दी है, जिसमें उसका ही नुकसान है, जबकि सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को हुआ है। हालांकि मप्र की मोहन यादव सरकार अभी भी यही दावा कर रही है कि हमारा नुकसान में भी नफ़ा ही है। प्रदेश में नर्मदा आंदोलन की पुरोधा रही मेधा पाटकर ने इस मामले में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि वह सच्चाई क्या है, यह जनता को बताएं। क्या मप्र ने अपना दावा छोड़ दिया है? सुश्री पाटकर ने पूरे समझौते पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि सरदार सरोवर परियोजना में मध्य प्रदेश के डूब क्षेत्र की 7669 करोड़ रुपये की वैध भरपाई और पुनर्वास के लिए 2900 करोड़ रुपये के दावे की अनेकड़ें हुई हैं। विवाद में मध्य प्रदेश में जलमग्न हुई वन भूमि, शासकीय भूमि और अन्य सार्वजनिक संसाधनों की भरपाई का मुद्दा शामिल है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र लगातार गुजरात से कानूनी रूप से अपेक्षित वित्तीय सहायता की मांग करते रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गुप्तमंत्री और जल संधान मंत्री की मध्यस्थता से हुए समझौते को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।

मेधा पाटकर ने कहा कि समझौते का अधिकृत ब्यूरा सार्वजनिक नहीं है, लेकिन प्रचारित खबरों में विरोधाभास हैं। उन्होंने परिप्रेक्ष्य को जानने और स्पष्टता की मांग करते हुए कहा कि किसी भी समझौते में मप्र सरकार और विस्थापितों के अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में जब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 90 मीटर तक सीमित थी, तब मध्य प्रदेश सरकार ने परियोजना से होने वाली क्षति के लिए 281.46 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। इस राशि में वन क्षेत्र के लिए 112.51 करोड़ रुपये, सरकारी भूमि के लिए 157.61 करोड़ रुपये और जलमग्न वन भूमि के लिए 11.34 करोड़ रुपये शामिल थे। इसके बाद बांध की ऊंचाई बढ़ाकर 110 मीटर और फिर 121.92 मीटर की गई। वर्ष 2014 से बांध की ऊंचाई में और वृद्धि की गई और 2017 में इसे 138.68 मीटर कर दिया गया। बांध की ऊंचाई बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में डूब क्षेत्र का विस्तार होता गया, जिससे बड़ी मात्रा में वन भूमि, सरकारी भूमि, कृषि क्षेत्र और अन्य प्राकृतिक संसाधन जलमग्न हुए। इससे राज्य को होने वाली क्षति पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई। विस्थापित गांवों की संख्या 2019 से 192 और एक नगर साबित हुई। 2023 में पुनर्निश्चित बैकवॉटर स्तरों के आधार पर हजारों परिवारों को ‘पुनर्वास के लिए अपात्र’ घोषित कर दिया गया, जिससे उनकी स्थिति और निगड़ गई। इसी वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने जलमग्न भूमि और अन्य प्रभावित परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कराया। 2019-2020 के आधार पर तैयार इस पुनर्मूल्यांकन के अनुसार, राज्य ने अपने डूब क्षेत्र की भरपाई के दावे को बढ़ाकर 7,669 करोड़ रुपये कर दिया। इस दावा बढ़े हुए डूब क्षेत्र और वर्तमान मूल्य के अनुरूप वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया था। 30 साल से अटकें इस मामले पर 7 जुलाई को दिल्ली में समाधान हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश को मुआवजा मिलना तो दूर, उट्टा गुजरात को 231.80 करोड़रुपए चुकाने पड़े।। यह तो न्याय मिलने की जगह अन्याय होने जैसी स्थिति है, लेकिन मप्र सरकार इसके खिलाफ आवाज उठाने की जगह जो हुआ, उसे ही फायदेमंद बता रही है। इससे संदेह और गहरा गया है।



फुटबॉल मुकाबले के राउंड ऑफ़ 16 में पैराग्वे की हार के बाद बिफरी वहां की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला ने फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे को लेकर बेहूदा नस्लीय टिप्पणियों की और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर अपमानजनक बातें कहीं। इसे लेकर स्वाभाविक ही था कि लोग खिन्न हुए, कुछ नाराज भी हुए, मगर जैसा कि होता है जल्दी ही इसे एक ‘विवाद’ बताया जाने लगा । एम्बापे के जवाबी जुमले को अमारिला के अपराधिक शब्दों के बराबर रखकर पश्चिमी मीडिया अपना खेल खेले लगा ।

कालों और अरवतों के प्रति यह द्वेष नया नहीं है बहुत पुराना है । लुतेरों जब इतिहास लिखते हैं तब सिर्फ इतिहास भर नहीं लिखते : वे भाषा भी गढ़ते हैं । मनुष्यता के शिकार में की गयी अपनी हिंसक, बर्बर, जघन्य और घोर आपराधिक ज्वायदतियों पर पर्दा डालने के लिए भाषा को भी नुकीले खंजर की तरह वापरते हैं। दुष्टई को प्रचलन में लाकर आम बना देते हैं। जैसे जो चीज खराब है वह नियमत: काली होगी : काले कानून, काली करतूतें, कालिख पोत देना, मुंह काला कर देना । जिस तरह वर्चस्वकारी दर्शन और विचार वही होता है जो शासकवर्ग के होते हैं : इसी तरह भाषा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ , कहावतें यहाँ तक कि व्याकरण भी वे ही कमबख्त तय करते हैं ।

हिन्दुस्तानियों - इस पूरे प्रायद्वीप - को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं। अपने यहाँ की, किसी भी भाषा की गालियों, कहावतों पर निगाह डाल लीजिये पता चल जाएगा। उधर वाले कुटित आत्ममुग्ध अमूमन रंग से खेलते हैं, इधर वालों के पास रंग के अलावा वर्ण है, जाति है, स्त्री है, यहाँ तक कि शारीरिक विकलांगता और रोग भी हैं। सेलेस्टे अमारिला के मुँह से निकला गरल इसी का प्रवाह था।

मगर मादाम यह भूल गयी कि सत्य वह होता है जो तथ्यों में दर्ज और खुली आँखों से दृष्ट्य्य होता है । वे यह भी भूल गयीं कि जिस एम्बापे की अफ्रीकी देशों से जुड़ी जड़ें उन्हें चुभ रही हैं। कैमरून के पिता और अल्जीरिया की माँ का

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धी परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।	
प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोक्किल संपादक (मध्यप्रदेश) विनोद तिवारी वरिष्ठ संपादक पंकज शुक्ला प्रबंध संपादक अरुण पटेल (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा) RNI No. MPJHIN/ 2003/ 10923, Ph.No. 0755-2422692, 4059111 Email- subahsaverenews@gmail.com	
‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।	



भारत को सभ्य बनाने आए अंग्रेज तो असभ्य थे ही क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में लूटपाट और दमन की ऐसी सभ्यता का विकास किया जिससे मुक्त होने में न जाने कितने वर्ष लगे। लेकिन रामराज्य कायम करने और सनातन धर्म की स्थापना का एक नास्टैलजिया (अतीत मोह) पेश करके संघ परिवार इस सभ्यता के साथ जो कर रहा है वह तो और भी भयानक है। संघ परिवार का आख्यान इन मान्यताओं पर आधारित था कि भारत में रहने वाला अल्पसंख्यक समाज हिंसक, क्रूर और असभ्य है। उसकी देशभक्ति भी सदिध है। जबकि हिंदू समाज उदार, सभ्य और देशभक्त है। इसलिए हिंदू खतरे में है। इसी के साथ उसका यह मानना है कि समाजवाद, साम्यवाद, समता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र और संविधानवाद के विचार विदेशी यानी यूरोप से आए हैं इसलिए वे भारत के लिए ग्राह्य नहीं हो सकते। इन्हीं आख्यानो को आधार बनाकर संघ परिवार महत्व और अर्थ की संरचनाओं पर कब्जा करके एक नई सभ्यता का निर्माण करना चाहता है। हालांकि इस दौरान वह यह भूल जाता है कि उसके भीतर नाजियों और फासीवादियों की प्रशंसा का जो भाव भरा है वह कहीं से भी स्वदेशी नहीं है। न ही आज अमेरिका और इजराइल के युद्धोन्मादी नेतृत्व की निकटता एक सभ्यता निर्माण में सहायक हो सकती है।

लेकिन संघ परिवार के सौ साल पूरे होने पर और केंद्रीय सत्ता में लगभग डेढ़ दशक तक बैठने के बाद और देश के अधिकतम राज्यों में सरकार चलाने और कुछ में तो दो दशक तक सत्ता पर कायम रहने के बाद देश का जो साम्थ्यतिक परिदृश्य बना है वह कहीं से भी सभ्यता की ओर नहीं जा रहा है। बल्कि भारत को असभ्य बनाने और वैश्विक स्तर पर कायम हो रही असभ्यता में सहायक बनने जा रहा है। मामला महज अयोध्या के राममंदिर में चढ़ावा चोरी (डकैती) का नहीं है, मामला उस पर कुतर्क करने और उसे भेजेज करने का है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत तो राम राम कहते हुए भागते दिखे लेकिन उनके दूसरे नंबर के पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि हिंदू विरोधी और राष्ट्रविरोधी लोग इसका इस्तेमाल हिंदू आस्था को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं उसे रोकने के लिए धैर्य चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू समाज के इसी धैर्य ने उसे लंबे समय तक अन्याय के विरुद्ध बोलने और समता और स्वतंत्रता पर आधारित समाज बनाने से रोके रखा। जो समाज अपने आंतरिक अन्याय से लड़कर उसे मिटाने का साहस न कर सके उसे निरंतर असभ्यता के गर्त में जाने से

अमारिला की टिप्पणी

बादल सरोज

लेखक लोकजन के सम्पादक हैं।

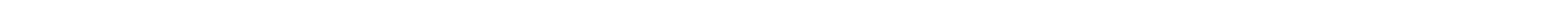
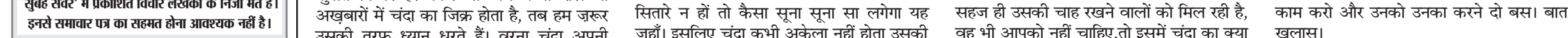
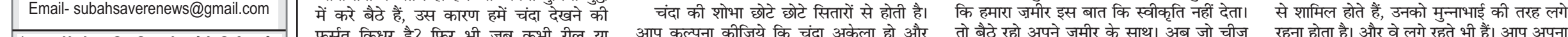
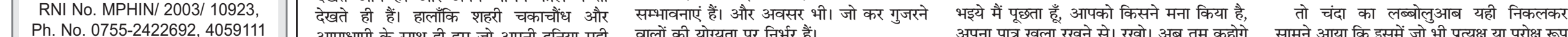
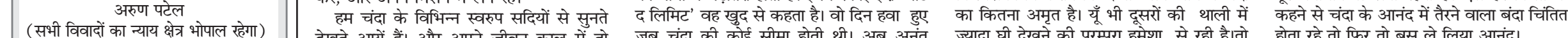
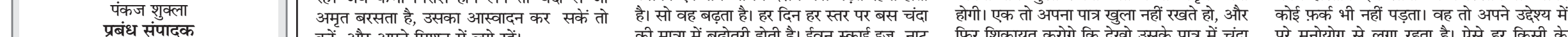
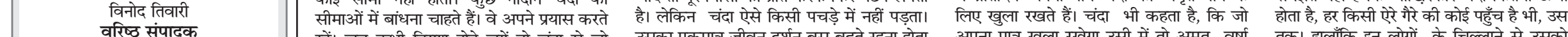
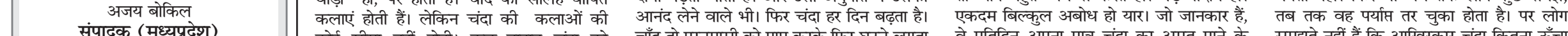
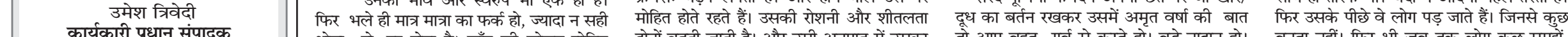
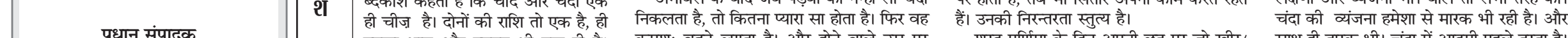
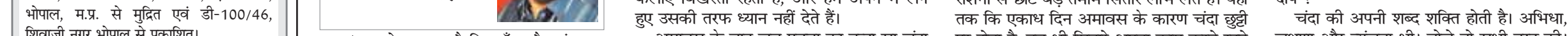
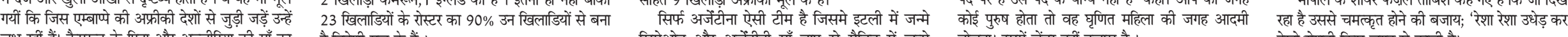
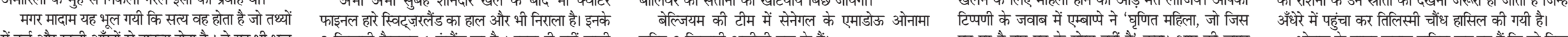
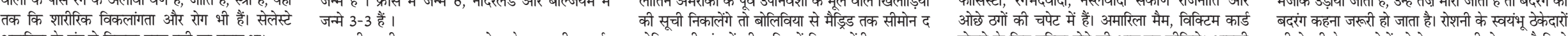
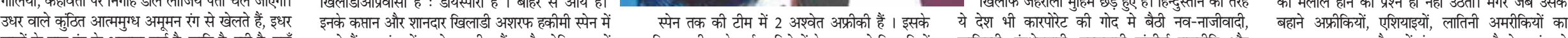
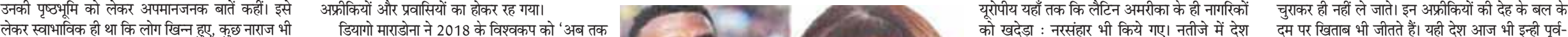
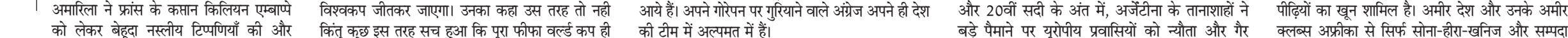
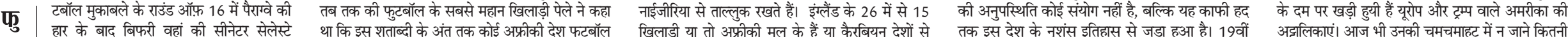
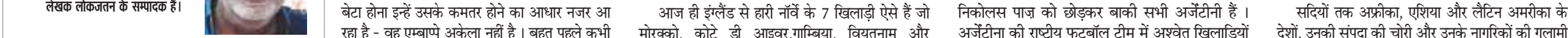
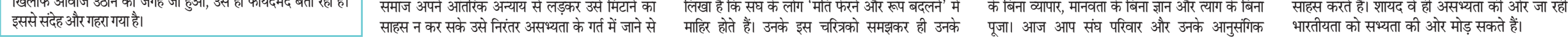
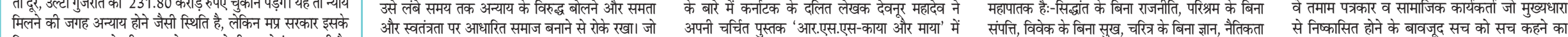
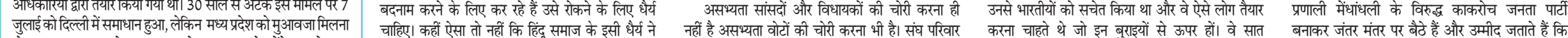
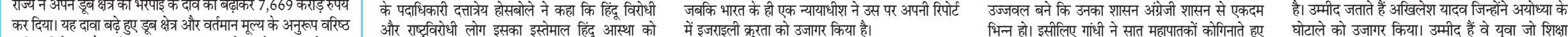
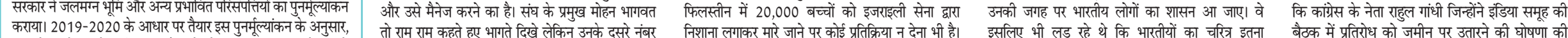
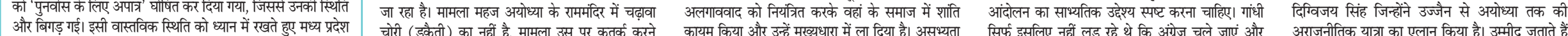
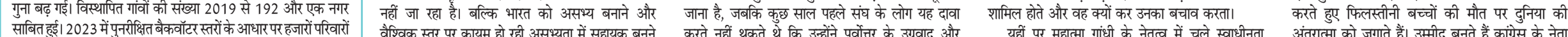
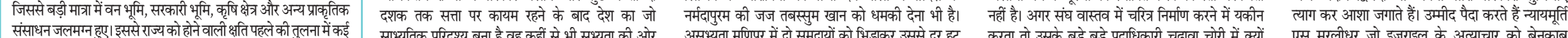
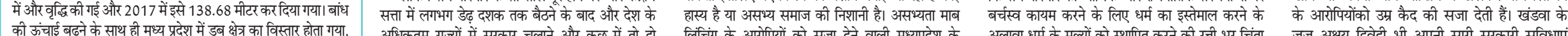
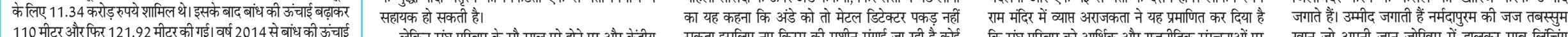
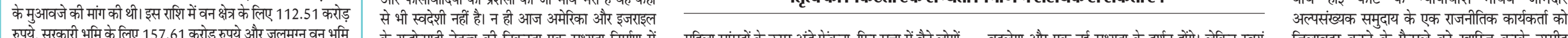
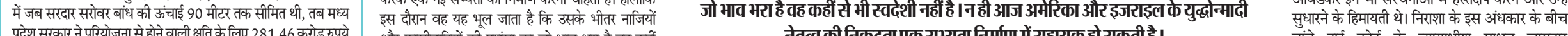
फुटबॉल मुकाबले के राउंड ऑफ़ 16 में पैराग्वे की हार के बाद बिफरी वहां की सीनेटर सेलेस्टे अमारिला ने फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे को लेकर बेहूदा नस्लीय टिप्पणियों की और उनकी पृष्ठभूमि को लेकर अपमानजनक बातें कहीं। इसे लेकर स्वाभाविक ही था कि लोग खिन्न हुए, कुछ नाराज भी हुए, मगर जैसा कि होता है जल्दी ही इसे एक ‘विवाद’ बताया जाने लगा । एम्बापे के जवाबी जुमले को अमारिला के अपराधिक शब्दों के बराबर रखकर पश्चिमी मीडिया अपना खेल खेले लगा ।

कालों और अरवतों के प्रति यह द्वेष नया नहीं है बहुत पुराना है । लुतेरों जब इतिहास लिखते हैं तब सिर्फ इतिहास भर नहीं लिखते : वे भाषा भी गढ़ते हैं । मनुष्यता के शिकार में की गयी अपनी हिंसक, बर्बर, जघन्य और घोर आपराधिक ज्वायदतियों पर पर्दा डालने के लिए भाषा को भी नुकीले खंजर की तरह वापरते हैं। दुष्टई को प्रचलन में लाकर आम बना देते हैं। जैसे जो चीज खराब है वह नियमत: काली होगी : काले कानून, काली करतूतें, कालिख पोत देना, मुंह काला कर देना । जिस तरह वर्चस्वकारी दर्शन और विचार वही होता है जो शासकवर्ग के होते हैं : इसी तरह भाषा, मुहावरे, लोकोक्तियाँ , कहावतें यहाँ तक कि व्याकरण भी वे ही कमबख्त तय करते हैं ।

हिन्दुस्तानियों - इस पूरे प्रायद्वीप - को यह याद दिलाने की जरूरत नहीं। अपने यहाँ की, किसी भी भाषा की गालियों, कहावतों पर निगाह डाल लीजिये पता चल जाएगा। उधर वाले कुटित आत्ममुग्ध अमूमन रंग से खेलते हैं, इधर वालों के पास रंग के अलावा वर्ण है, जाति है, स्त्री है, यहाँ तक कि शारीरिक विकलांगता और रोग भी हैं। सेलेस्टे अमारिला के मुँह से निकला गरल इसी का प्रवाह था।

मगर मादाम यह भूल गयी कि सत्य वह होता है जो तथ्यों में दर्ज और खुली आँखों से दृष्ट्य्य होता है । वे यह भी भूल गयीं कि जिस एम्बापे की अफ्रीकी देशों से जुड़ी जड़ें उन्हें चुभ रही हैं। कैमरून के पिता और अल्जीरिया की माँ का

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धिविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धी परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।	
प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोक्किल संपादक (मध्यप्रदेश) विनोद तिवारी वरिष्ठ संपादक पंकज शुक्ला प्रबंध संपादक अरुण पटेल (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा) RNI No. MPJHIN/ 2003/ 10923, Ph.No. 0755-2422692, 4059111 Email- subahsaverenews@gmail.com	
‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।	



नाउम्मीद होने से काम नहीं चलने वाला

कौन रोक सकता है।

लेकिन असभ्यता का प्रदर्शन अयोध्या तक सीमित नहीं है। वह उस समय भी दिखता है जब दिल्ली से सटे लोनी इलाके में एक मुस्लिम युवक तालाब में नहाने के लिए निकलता है, उसकी बाइक से किसी कार वाले को खरोंच लग जाती है और उसे पीट पीट कर मार डाला जाता है। यह प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद विपक्षी दल तुगमूल कांग्रेस के नेताओं के साथ किए जा रहे व्यवहार से होता है। नेताओं के कपड़े उतार कर और उनके गले में जूता डालकर घुमाया जाना कौन सी लोकतांत्रिक सभ्यता और संस्कृति का द्योतक है। सांसदों को गिराकर मारना और

संघ परिवार का आख्यान इन मान्यताओं पर आधारित था कि भारत में रहने वाला अल्पसंख्यक समाज हिंसक, क्रूर और असभ्य है। उसकी देशभक्ति भी सदिग्ध है। जबकि हिंदू समाज उदार, सभ्य और देशभक्त है। इसलिए हिंदू खतरे में है। इसी के साथ उसका यह मानना है कि समाजवाद, साम्यवाद, समता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र और संविधानवाद के विचार विदेशी यानी यूरोप से आए हैं इसलिए वे भारत के लिए ग्राह्य नहीं हो सकते। इन्हीं आख्यानो को आधार बनाकर संघ परिवार महत्व और अर्थ की संरचनाओं पर कब्जा करके एक नई सभ्यता का निर्माण करना चाहता है। हालांकि इस दौरान वह यह भूल जाता है कि उसके भीतर नाजियों और फासीवादियों की प्रशंसा का जो भाव भरा है वह कहीं से भी स्वदेशी नहीं है। न ही आज अमेरिका और इजराइल के युद्धोन्मादी नेतृत्व की निकटता एक सभ्यता निर्माण में सहायक हो सकती है।

लेकिन संघ परिवार के सौ साल पूरे होने पर और केंद्रीय सत्ता में लगभग डेढ़ दशक तक बैठने के बाद और देश के अधिकतम राज्यों में सरकार चलाने और कुछ में तो दो दशक तक सत्ता पर कायम रहने के बाद देश का जो साम्थ्यतिक परिदृश्य बना है वह कहीं से भी सभ्यता की ओर नहीं जा रहा है। बल्कि भारत को असभ्य बनाने और वैश्विक स्तर पर कायम हो रही असभ्यता में सहायक बनने जा रहा है। मामला महज अयोध्या के राममंदिर में चढ़ावा चोरी (डकैती) का नहीं है, मामला उस पर कुतर्क करने और उसे भेजेज करने का है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत तो राम राम कहते हुए भागते दिखे लेकिन उनके दूसरे

केन-बेतवा परियोजना

प्रो. आरके जैन ‘अरिजीत’

लेखक शिक्षाविद हैं।



केन-बेतवा परियोजना का प्रमुख हिस्सा दौधन बाँध है, जो पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर प्रस्तावित है। इससे लगभग 9 हजार हेक्टेयर भूमि, जिसमें कोर क्षेत्र का करीब 41.41 वर्ग किलोमीटर और बफर क्षेत्र शामिल हैं, डूबेगी। करीब 23 लाख पेड़ प्रभावित होने और केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलकर जल बेतवा में भेजने की आशंका है। सरकार के अनुसार इससे 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल और 1०3 मेगावाट बिजली मिलेगी। लेकिन गोंड और कोल आदिवासियों के लिए यह केवल विकास नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल है। उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, आजीविका और पहचान का आधार है।

वादों और जमीनी हकीकत की दूरी ने चिता आंदोलन फिर सुलगा दिया। प्रशासन के आशवासन के बावजूद कई गाँवों में मकान तोड़े गए, बिजली कनेक्शन काटे गए, स्कूल ढहाए गए और विरोध करने वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। दिव्या अहिरवार, लक्ष्मी आदिवासी सहित कई महिलाएँ विरोध में डूटी रहीं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर अनशन पर बैठे। उनका दावा है कि 7,000 से अधिक परिवार (लगभग 35-50 हजार लोग) विस्थापन की कगार पर हैं। उनके अनुसार संकट केवल घरों का नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का है। सवाल है-यदि विकास की कीमत आदिवासी समाज चुकाए और लाभ दूसरों को मिले, तो क्या यह न्यायपूर्ण विकास कहलाएगा?

इस संघर्ष का दायरा केवल विस्थापन नहीं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र तक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डूबने की आशंका है, जिससे बाघों की पुनर्स्थापना, घड़ियाल संरक्षण और गिद्धों के प्राकृतिक घोंसले संकट में पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वृक्ष कटाई और पारिस्थितिकी परिवर्तन से क्षेत्रीय वर्षा में करीब 12 प्रतिशत कमी आ सकती है। केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने की आशंका है। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिक भी इसके प्राकृतिक तंत्र पर



प्रभाव की चेतावनी दे चुके हैं। इसलिए आदिवासियों का ‘जंगल हमारा, नदी हमारी’ कहना विकास विरोध नहीं, बल्कि प्रकृति और भविष्य की चिंता है।

किसी भी विस्थापन की सबसे बड़ी कीमत आँकड़ें नहीं, इंसानी जिंदगियाँ चुकाती हैं। केन-बेतवा परियोजना भी इसी सच्चाई के सामने है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 7 हजार से अधिक परिवार प्रभावित होंगे और 22 गाँव डूब क्षेत्र में समा जाएँगे। पुनर्वास को लेकर असंतोष है। किसी को साढ़े बारह लाख, तो किसी को केवल साढ़े

सात लाख रुपये मुआवजा मिल रहा है। वयस्क सदस्यों को अलग परिवार का दर्जा देने की माँग अधूरी है। आदिवासी समाज नकद नहीं, ‘भूमि के बदले भूमि’ चाहता है, क्योंकि जंगल और खेत उसके जीवन का आधार हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। पर्याप्त सूचना बिना मकान तोड़े जाने से प्रशासन और समाज के बीच भरोसे की खाई गहरी हुई है।

तस्वीर का दूसरा पहलू भी अहम है। सरकार का तर्क

है कि भविष्य की जल जरूरतों के लिए बड़े समाधान जरूरी हैं। सिंचाई, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि किसी परियोजना का मूल्य केवल लाभ से तय होगा या उसकी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत से भी। केन-बेतवा परियोजना ने फिर बहस छेड़ी है कि नदी जोड़ो योजनाएँ तभी सफल होंगी, जब वे स्थानीय परिस्थितियों, पारिस्थितिकी और समाज की जरूरतों के अनुरूप हों। केवल इंजीनियरिंग समाधान, प्रकृति और

समुदाय की सहमति बिना, स्थायी नहीं हो सकते। विकास तभी सार्थक है, जब लाभ और कीमत का न्यायपूर्ण संतुलन हो।

बड़ी परियोजनाओं के साथ छोटे, टिकाऊ विकल्प भी जरूरी हैं। विशेषज्ञ वर्षा जल संचयन, छोटे बाँध, जलग्रहण प्रबंधन और स्थानीय जल संरक्षण को बेहतर समाधान मानते हैं। सवाल है कि मध्य प्रदेश अपने जंगलों, वन्य संपदा और जल संसाधनों की कीमत चुका रहा है, जबकि लाभ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने भी परियोजना की पर्यावरणीय और आर्थिक व्यवहार्यता पर गंभीर आपत्तियाँ दर्ज की थीं, लेकिन उन्हें महत्व नहीं मिला। यदि बड़े निर्णयों में वैज्ञानिक चेतावनियाँ, स्थानीय अनुभव और न्यायपूर्ण पुनर्वास उपेक्षित रहें, तो विकास का दावा संदेह के घेरे में आता है। लोकतंत्र की शक्ति केवल निर्णय में नहीं, असहमति सुनने में भी है।

पन्ना और छतरपुर से उठता यह संघर्ष अब केवल कुछ गाँवों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठता है कि भारत का विकास प्रकृति और मानव के संतुलन के साथ होगा या जंगलों और संस्कृतियों की कीमत पर। आदिवासी महिलाओं का संघर्ष केवल मुआवजे का नहीं, बल्कि सम्मान, अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का है। सरकार को पारदर्शी पुनर्वास, प्रभावी पर्यावरणीय समीक्षा और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप प्लान के तहत 47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन विकास प्रस्तावित है। इतिहास बाँधों की ऊँचाई नहीं, बल्कि कमजोर वगों के साथ राष्ट्र के व्यवहार को याद रखता है। विकास तभी टिकाऊ होगा, जब वह प्रकृति और लोगों की सहमति से आगे बढ़े।

थोड़ा बाहर तो निकलिये जनाब



देखने में आया। उम्मीद है प्रदेश में अन्य जगहों तथा अन्य राज्यों (अपवाद स्वरूप छोड़कर) में भी यही स्थिति निर्मित हुई होगी। हालाँकि,खबरेँ यह भी आ रही है कि पिछले तीन-चार दिनों से बादल तो छा रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे। उम्मीद है जल्द बादल उमड़ घुमड़ कर बरसेंगे।

हम कितनी भी बड़ी- बड़ी बातें कर लें लेकिन आज भी देश का कृषि सेक्टर हमारी अर्थ व्यवस्था का प्रमुख कारक है। हरे-भरे खेत और किसानों के चेहरों पर खुशी देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला वक़्त कैसा

में एक रणनीति के तहत काम करना चाहिये।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि किसानों को जरूरत के खाद बीज समेत अन्य कृषि आदान समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्हें यूरिया आदि खाद और बीज के लिये भटकने नहीं दिया जाना चाहिये, ऐसे प्रबंध नितांत आवश्यक हैं। हालांकि इस बार वैश्विक परिदृश्य, युद्ध की स्थिति को लेकर अनिश्चितता के चलते खाद (यूरिया) की किल्लत स्वाभाविक रूप से सामने आई। अच्छा होगा भविष्य के

मानसून और मौसम के जानकार कुछ भी भविष्यवाणी कर दें हमारे यहां किसान भाइयों का अपना गणित, अपना पूर्वानुमान तथा अपना खुद का आकलन रहता है। हमारे यहां प्रचलित पंचांग भी सटीक अनुमान ही बतलाते हैं। सो, एक पखवाड़े पहले ही किसानों ने खरीफ फसलों के लिये जरूरी तैयारियां कर ली थी। मानसून पूर्व बारिश के चलते अनेक जगह बोवनी शुरू हो चुकी थी। अब खेतों में फसलें अंकुरित हो चली हैं तो कहीं और भी ज्यादा बढ़वार दिखाई दे रही है।

रहेगा। इस यात्रा के दौरान जो फि़क्र सामने आई वो थी कि धीरे- धीरे खेती का रकबा घटता क्यों जा रहा है? उसकी जगह राजधानी से लेकर आर्थिक राजधानी इंदौर तक जगह-जगह खेतों पर कहीं- कहीं पर भव्य इमारतें तो कहीं मैरिज गार्डन , रिसॉर्ट, होटल्स आदि तनते जा रहे हैं। निश्चित ही यह चिंता की विषय होना चाहिये। इस बात का हिसाब किताब तो होना चाहिये कि हाल के वर्षों में खेती योग्य कितनी ज़मीन पर कमर्शियल गतिविधियां शुरू की गई है। क्या कुछेक किसानों, खासकर नई पीढ़ी के युवाओं का खेती से मोहभंग तो नहीं होता जा रहा है? अगर ऐसा है तो इस पर जिम्मेदारों को ध्यान देकर किसान परिवारों के युवाओं को खेती- किसानी की ओर उन्मुख करने की दिशा

लिये रणनीति बनाकर तदनु रूप प्रयास किये जायें।

सो, बड़े शहरों के सुविधाभोगी लोगों को शहर से बाहर निकलकर भी इस मौसम में सुरुष्य प्राकृतिक दृश्यों के साथ खेती - किसानी के हालात की जानकारी लेते रहना चाहिये। महज अपनी जरूरत के गेहूँ, दाल-भात, सब्जियां शहर में बैठे- बिठाये खरीदने से आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो सकती बल्कि इन्हें आप तक पहुंचाने में कितना लंबा और थकाऊ प्रोसेस चलता है इस बात से अवगत तथा अवैयर होना भी आज की जरूरत है। आखिर तेजी से बढ़ता शहरीकरण धीरे- धीरे खेती की ओर उपेक्षा के भाव का विस्तार ही तो नहीं कर रहा, यह देखना सरकारों के साथ जागरूक नागरिकों का भी कर्तव्य है।

सामयिक

विवेक मिश्रा



बहुगष्टीय परियोजनाएँ, देशों के मध्य व्यवसायिक उत्कर्ष, सुगम नागरिक संपर्क और सामरिक श्रेष्ठता की स्थापत्य कलाकृति होती हैं। स्वकेंद्रित प्रभुत्व के सामने, यह समत्व के समन्वयकारी विस्तार को मान्यता देती है। जैसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सैद्धांतिक प्रतिकार में खड़ी भारत की लाइन ऑफ़ क्रेडिट योजना। यद्यपि इन परियोजनाओं की सफलता, प्रारंभिक सैद्धांतिक मान्यता से कहीं बढ़कर वास्तविक निर्माण तीव्रता पर निर्भर करती है। विदेश नीति में भी निर्माण गति का विशेष महत्व है। रणनीतिक क्षेत्रों तक त्वरित, सरल व सुदृढ़ शांतिपूर्ण उपस्थिति, सुरक्षा की प्रथम दीवार बनती है।

इन दिनों बांग्लादेश के द्वारा मोंगला पोर्ट के विनिर्माण विकास अधिकार भारत से वापस लेकर, चीन को सौंपे जाने की चर्चाएं चहुंओर हो रही है। कारणों में,वर्ष 2024 शेख हसीना सरकार के निष्काषन को प्रथान्यता के साथ उठाया गया, लेकिन इस शोर में हमने उस तथ्य का वेष्टन किया है, जो हमारे क्रियान्वयन के घोंघा चाल से उजागर होता है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के तहत, तय हुए अनुबंध में, भारत को 110 एकड़ क्षेत्र पर आर्थिक गलियारे को विकसित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। भारत की सुस्पष्ट लाइन ऑफ़ क्रेडिट योजना से इसका वित्तपोषण होना था। इस योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत निर्माण सामान व सेवाएं भारत से प्राप्त करना होता है। भारत सरकार से जारी फंड की प्राप्ति पर, संबंधित देश औपचारिक निविदा जारी कर आवंटन करते हैं। सरकार से सरकार (जी टू जी) स्तर पर हुए, मोंगला

सामरिक प्रभुत्व निर्धारित करता है निर्माण कार्यों की गति

इन दिनों बांग्लादेश के द्वारा मोंगला पोर्ट के विनिर्माण विकास अधिकार भारत से वापस लेकर, चीन को सौंपे जाने की चर्चाएं चहुंओर हो रही है। कारणों में ,वर्ष 2024 शेख हसीना सरकार के निष्काषन को प्रधान्यता के साथ उठाया गया, लेकिन इस शोर में हमने उस तथ्य का वेष्टन किया है, जो हमारे क्रियान्वयन के घोंघा चाल से उजागर होता है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री की बांग्लादेश यात्रा के तहत, तय हुए अनुबंध में, भारत को 110 एकड़ क्षेत्र पर आर्थिक गलियारे को विकसित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था । भारत की सुस्पष्ट लाइन ऑफ़ क्रेडिट योजना से इसका वित्तपोषण होना था । इस योजना के अंतर्गत 75 प्रतिशत निर्माण सामान व सेवाएं भारत से प्राप्त करना होता है।

पोर्ट विकास समझौते को मूर्त रूप देने के लिए एक लंबी जटिल कागजी कार्रवाई चली, जिसके बाद सन 2018 में भारत सरकार से फंड जारी हुआ । बांग्लादेश की ओर से 2019 में सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति के संबंध में कड़े प्रावधानों को प्रस्तावित किया गया। जिनमें

कंसल्टेंसी समूहों से ऊँचे टर्न ओवर, नेटवर्थ, वृहद् कार्यक्षेत्र और विशिष्ट तकनीकी अनुभव की माँग अपेक्षित की गई । इन शर्तों को पूर्ण करने की स्थिति में, अडानी ग्रुप और एल. एन. टी. समूह को छोड़कर कोई भी अन्य भारतीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी समूह सक्षम नहीं थे। योग्यता के बावजूद इन दोनों बड़े समूहों का भागीदारी न दिखाना, तात्कालिक भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों, लाभांश और सीमित स्वतंत्र कार्यशैली के वजह से था। विपक्ष, सरकार पर अडानी समूह को फायदा पहुंचाने के आरोपों के साथ हावी था, स्वयं अडानी समूह भी इस प्रोजेक्ट में सरकार द्वारा हीरानंदानी ग्रुप को नामित कर देने के बाद सलाहकार फर्म के तौर पर, मात्र 80 करोड़ के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने को इच्छुक न था। जबकि एल.एन.टी. समूह लाइन ऑफ़ क्रेडिट जैसी योजनाओं की बाध्यकारी नियमावली में कार्य करने के बजाए स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भरोसा रखता है। इस सब का अंततोगत्वा परिणाम यही निकला कि 9 वर्षों के लम्बे

विलंब और 2024 में शेख हसीना सरकार के निष्कासन के साथ उपजी भारत विरोधी भावनाओं में मोंगला पोर्ट के विकास अधिकार चीनी सरकारी कम्पनियों के ओर बह गए।

पड़ोसी देशों में रणनीतिक महत्व वाले स्थानों पर



पिछड़ते भारतीय प्रोजेक्ट हमारी वैश्विक कूटनीतिक बढ़त को बेहद कमजोर कर देते हैं। उदाहरण सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य करने को इच्छुक न था। जबकि एल.एन.टी. समूह लाइन ऑफ़ क्रेडिट जैसी योजनाओं की बाध्यकारी नियमावली में कार्य करने के बजाए स्वतंत्र रूप से कार्य करने में भरोसा रखता है। इस सब का अंततोगत्वा परिणाम यही निकला कि 9 वर्षों के लम्बे

पूरा न हो सका। इसके बाद 2019 में कोरोना महामारी और म्यांमार में साल 2021 के सैन्य तख्ता पलट से निर्मित अनिश्चितताओं के चलते, यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज भी पूर्ण होने की राह देख रहा है। म्यांमार से जुड़ा एक और अहम, भारत - म्यांमार - थाईलैंड राजमार्ग का कार्य , 2002 में विचारित, 2012 से आरंभित और 2016 को पूर्णता के प्रति लक्षित था। भारत इसे कंबोडिया,लाओस व वियतनाम तक प्रसारित कर ईस्ट वेस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का रूप देना चाहता है , हाल फिलहाल यह आशंकाओं से घिरा है । वहीं चीन इसके समानांतर सीमेक (चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर) के प्रतिस्पर्धी निर्माण में लगा है । भारत द्वारा भूटान में मांगदेखू और पुनातसांगछु - II जैसी पनबिजली परियोजनाओं को पूरा करने में क्रमशः 9 वर्ष और 15 वर्ष का लंबा समय लगा था। वहीं पुनातसांगछु - I परियोजना, भूस्खलन और

तकनीकी विरोधाभासो से जूझते हुए, लगभग 21 वर्षों बाद पूर्णतः संचालित हो सकेगी। जबकि इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए, चीन अपनी उन्नत अत्याधुनिक तकनीक जैसे मेगा टी.बी.एम. मशीन, सेटेललाइट मैपिंग, 3डी जी.आई. एस. मॉडलिंग द्वारा कमजोर चट्टानों की पहचान, स्खलन के बाद हाई स्पीड केमिकल ग्राउंटिंग और रोबोटिक्स इफोसमेंट की मदद से, यह सभी निर्माण

कार्य 7 से 9 वर्षों में पूर्ण करने का सामर्थ्य रखता है। सामरिक हितों के यह प्रोजेक्ट सिर्फ पड़ोसी देशों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि भारत में भी निकोबार द्वीप समूह का रणनीतिक विकास, अरुणाचल में चीन की चुनौतियों के जवाब में प्रस्तावित कमला,दिबांग, कलई जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं। जिनका समय अवधि में पूरा होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए निर्णायक रहेगा। निर्माण कार्यों की देरी, लागत में तो बढ़ोतरी करती ही है, अनिश्चित भौगोलिक विपदाओं की पुनरावृत्ति को अधिक अवसर देती है, साथ ही तेजी से बदलते वैश्विक कूटनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करने का स्थान सौंपती है। आज भारत सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और संस्कृति के पंच सिद्धांतों पर आधारित ‘नेबरहुड फर्स्ट’ और ‘लूक ईस्ट’ पॉलिसी को मान्यता देता है। अपेक्षाकृत अधिक भागीदारीपूर्ण, सुरक्षित और किफायती होने के बावजूद यह भारतीय योजनाएं , पड़ोसी देशों में अपनी जटिल प्रक्रिया व दीर्घ कार्यावधि के कारण चीन की आक्रामक, महंगी लेकिन तेज निर्माण गति वाली बी.आर.आई जैसी योजनाओं से पिछड़ती नजर आती है। आवश्यक है कि, इन विषमताओं का सामना भारत सरकार प्रक्रियाओं को सरल व त्वरित बना कर एवं निर्माणाधीन कंपनियां लाभांश के अनुपातिक आंकलन से ऊपर उठकर राष्ट्रहितों के अनुकूल सैन्य चपलता से करें।

संक्षिप्त समाचार

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शहर में विकास कार्यों का किया निरीक्षण



बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने शनिवार को शहर का भ्रमण कर विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में चल रहे रिनोवेशन कार्य का निरीक्षण कर कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने प्रस्तावित नवीन सर्किट हाउस के संबंध में भी हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम डॉ. अभिजीत सिंह सहित हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश राज्य जूडो अकादमी में प्रवेश के लिए चयन ट्रायल आयोजित



बैतूल (निप्र)। खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश के तत्वावधान में शनिवार को स्थानीय शासकीय कन्या क्रीड़ा परिसर हमलपुर में मध्य प्रदेश राज्य जूडो अकादमी भोपाल में प्रवेश के लिए एक दिवसीय चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। इस चयन प्रक्रिया में बैतूल जिले के समस्त विकासखंडों से लगभग 50 जूडो खिलाड़ियों ने भाग लिया। भोपाल से आए खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रतिनिधि श्री गोविन्द रजाक प्रशिक्षक एवं श्री जयप्रकाश यादव प्रशिक्षक ने प्रतिभागी खिलाड़ियों के शारीरिक मापदंडों, फिटनेस और जूडो खेल कौशल का बारीकी से परीक्षण किया। जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी श्रीमती पूजा कुरील ने बताया कि इस ट्रायल का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रतिभाओं को तराशना है। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में सफल होने वाले खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश राज्य जूडो अकादमी, भोपाल में प्रवेश दिया जाएगा। अकादमी में चयनित खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल प्रशिक्षण के साथ-साथ निःशुल्क शिक्षा, आवास और डाइट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन कर सकें। प्रतिभा चयन कार्यक्रम को सफल बनाने में क्रीड़ा अधिकारी जनजातीय कार्य विभाग श्री विनय यादव, छात्रावास अधीक्षिका श्रीमती अनिता जौधलेकर एवं समस्त प्रशिक्षक, समस्त युवा समन्वयक खेल विभाग का विशेष सहयोग रहा।

कलेक्टर के त्वरित हस्तक्षेप से छात्र कृष्णा की टीसी में हुई त्रुटि का एक ही दिन में निराकरण

विदिशा (निप्र)। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता एवं आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के प्रति जिला प्रशासन की संवेदनशीलता का एक और उदाहरण सामने आया है। बलभद्र स्कूल, विदिशा के कक्षा दो में अध्ययनरतछात्र कृष्णा कुशवाह की ट्रांसफर सर्టిफिकेट (टीसी) में प्रवेश दिनांक गलत दर्ज होने की जानकारी मिलते ही कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने तत्काल संज्ञान लिया और जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता के निर्देशों के पालन में डीपीसी ने बिना विलंब किए बीआरसीसी को विद्यालय भेजा। मौके पर अभिलेखों का परीक्षण कर छात्र की टीसी में दर्ज प्रवेश दिनांक की त्रुटि का सुधार कराया गया। पूरी प्रक्रिया को प्रार्थमिकता देते हुए छात्रा की समस्या का उसी दिन निराकरण सुनिश्चित किया गया। इस त्वरित कार्रवाई से छात्र एवं उसके परिजनो को राहत मिली। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि भविष्य में उनकी पढ़ाई एवं प्रवेश प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए ऐसे मामलों में तत्पत्ता से कार्रवाई करते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शैक्षणिक अभिलेख तैयार करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाए, ताकि विद्यार्थियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

विद्युत चोरी पर सख्त कार्रवाई: आरोपी को एक वर्ष का कारावास, 65,267 का जुर्माना

विदिशा (निप्र)। विद्युत चोरी के मामलों में सख्त कार्रवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (विद्युत), विदिशा के न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास एवं 65,267 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय के इस निर्णय को विद्युत चोरी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, विदिशा के उपमहाप्रबंधक श्री श्रवण कुमार पटेल ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (विद्युत) माननीय श्री राजेश शर्मा के न्यायालय में विचारार्थीन प्रकरण क्रमांक स्‍खश्‍ख 921/2022 में आरोपी शिंगराम सिंह पुत्र गं‍बर‍ाव यादव, निवासी ग्राम विसो‍निया, तहसील एवं थाना शमशाबाद, जिला विदिशा को विद्युत चोरी का दोषी पाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के साधारण कारावास तथा 65,267 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के विरुद्ध कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत विशेष न्यायालय (विद्युत), विदिशा में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए दंडादेश पारित किया।

उदयपुर के सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सत्र आयोजित

छात्राओं को स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक



विदिशा (निप्र)। छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उदयपुर स्थित सीनियर गर्ल्स हॉस्टल में स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य

विभाग की टीम ने छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।

स्वास्थ्य शिविर के दौरान छात्राओं की सामान्य स्वास्थ्य जांच, रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, वजन, ऊंचाई तथा अन्य आवश्यक परीक्षण किए गए। चिकित्सकों ने छात्राओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद कर उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सुना और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया। जरूरतमंद छात्राओं को आगे की जांच एवं उपचार के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

परामर्श सत्र में विशेषज्ञों ने संतुलित आहार, स्वच्छता, नियमित व्यायाम, एनीमिया से बचाव, मासिक धर्म स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन तथा संक्रमण से बचाव जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने छात्राओं से किसी भी स्वास्थ्य समस्या को छिपाने के बजाय

समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की। इस अवसर पर छात्राओं को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी पीने, नियमित दिनचर्या अपनाने तथा व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि किशोरावस्था में सही स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका विस्तार से समाधान किया गया। छात्राओं ने इस प्रकार के स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता कार्यक्रमों को उपयोगी बताते हुए भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित किए जाने की आवश्यकता जताई। स्वास्थ्य विभाग एवं हॉस्टल प्रबंधन ने छात्राओं के बेहतर स्वास्थ्य और समग्र विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

विश्व जनसंख्या दिवस पर एएनएमटीसी प्रशिक्षण केन्द्र टिकारी में कार्यशाला आयोजित



बैतूल (निप्र)। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को एएनएमटीसी प्रशिक्षण केन्द्र टिकारी बैतूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ जगदीश घोरे ने बताया कि भारत शासन के

सके। प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ घोरे ने सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि इस संदेश को हर समुदाय तक पहुंचा कर सीमित संसाधनों और बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करें, ताकि लोग छोटा परिवार अपनाकर अपना और समाज के भविष्य को बेहतर बना सकें। छोटा परिवार रखने से संसाधनो का बेहतर उपयोग कर सकते हैं।

जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ राजेश परिहार ने परिवार कल्याण के विभिन्न साधनों की जानकारी देते हुए बताया कि अभियान के दौरान प्रत्येक लक्ष्य दम्पति को परिवार नियोजन के कोई न कोई साधन से सुरक्षित करें। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस अभियान की थीम मां और बच्चे की अच्छी सेहत के लिये गर्भधारण के लिए सही समय तथा गर्भावस्था के मध्य सही अंतर रखा जाना जरूरी है। कार्यशाला में प्रभारी शहरी चिकित्सा अधिकारी डॉ रत्नेश खांडे, उप जिला मीडिया अधिकारी श्री महेशराम गुबरेले, परिवार कल्याण प्रभारी श्री भगतसिंह उड्के, एपीएम श्री प्रकाश माकाड़े, सुपरवाइजर श्री कृष्णा पाटिल, एएनएम एवं आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे।



1500 रुपए के विवाद में युवक को अर्धनग्न कर पीटा

उधारी मांगने पर हुआ विवाद, डंडों से बेरहमी से मारपीट; आरोपियों का निकाला जुलूस

रह रहा था और घटना से दो दिन पहले ही नर्मदापुरम लौटा था। **अर्धनग्न कर डंडों से बेरहमी से पीटा**

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम के एसपीएम पुलिस क्षेत्र में 1500 रुपए के विवाद में एक युवक को अर्धनग्न कर डंडों से बेरहमी से पीटने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को आरोपियों को कोतवाली थाने लाने के बाद वारदात में इस्तेमाल डंडा बरामद कराने के लिए ग्वालटोली क्षेत्र ले जाया गया। इसके बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। घायल युवक की पहचान शुभम खंडारे (25) निवासी एसपीएम पुलिस, ग्वालटोली के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, शुभम ने करीब एक साल पहले आरोपी रोहित बाबरिया और विजय रैकवार, निवासी ग्वालटोली, से 1500 रुपए उधार लिए थे। वह लंबे समय से भोपाल में

रिश्तत प्रकरण में नटेरन के पटवारी संदीप यादव निलंबित

विदिशा (निप्र)। लोकायुक्त भोपाल द्वारा 30 हजार रुपये की रिश्तत लेते हुए ट्रैप किए जाने के बाद तहसील नटेरन के पटवारी हल्का क्रमांक-40 (रावन) के पटवारी संदीप यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। नटेरन एसडीएम श्री अजय प्रताप सिंह पटेल द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय नटेरन नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। साथ ही उनके पटवारी हल्का नंबर 40 (रावन) का प्रभारी श्री लेखन लोधी, पटवारी हल्का नंबर 42 (खाईखेडा) एवं पटवारी हल्का नंबर 05 (रायखेडी) का प्रभार श्री सुलभ समैया, पटवारी हल्का नंबर 06 (सकराई) को अतिरिक्त प्रभार अगामी आदेश पर्यंत तक सौंपा गया है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत शासकीय कन्या शाला में हुआ पौधारोपण

बैतूल (निप्र)। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की योजना मेरा युवा भारत बैतूल के द्वारा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत शासकीय कन्या शाला गंज बैतूल परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नर्मदा प्रसाद मिश्रा, ज्योति गौद, शिक्षक महेश गुजेले, राधेलाल बनखेडे व धनंजय सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। मेरा युवा भारत बैतूल के स्वयंसेवकों द्वारा विद्यालय परिसर में छायादार एवं फलदार पौधे लगाए गए। पौधारोपण के दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दौर में पेड़ लगाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। 'मेरा युवा भारत' के माध्यम से जिले भर में युवा मंडल, महिला मंडल और स्वयंसेवकों द्वारा लगातार पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही लगाए गए पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी स्वयं लेने का आग्रह किया गया। इस अवसर पर महेश गुजेले ने बताया कि पेड़ हमें ऑक्सीजन, छाया, फल, औषधि और शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं। पेड़ केवल पर्यावरण ही



नहीं बल्कि मानव जीवन के आधार हैं। राधेलाल बनखेडे ने अपने संबोधन में जल संरक्षण और वृक्ष संरक्षण को एक-दूसरे से जोड़ते हुए कहा कि यदि हम पेड़ बचाएंगे तभी जल बचेगा और जीवन बचेगा। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण की सामूहिक शपथ भी दिलाई।

कार्यक्रम के दौरान मेरा युवा भारत पोर्टल पर

एसडीएम-तहसीलदार ने किया कालियदेव झरने का निरीक्षण

सीहोर (निप्र)। इछावर एसडीएम श्रीमती स्वाति मिश्रा, तहसीलदार सुश्री आनामिका चतुर्वेदी सहित राजस्व, पुलिस एवं जनपद के अधिकारियों द्वारा कालियादेव वॉटरफॉल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने झरना स्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी ली और वॉटरफॉल पर आमजन के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध का पूर्णतः और सख्ती के साथ पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

विश्व पेपर बैग दिवस 2026 पर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

विदिशा (निप्र)। राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा द्वारा सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधि के अंतर्गत 14 एमपी बटालियन एनसीसी, विदिशा के सहयोग से विश्व पेपर बैग दिवस 2026 का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम की थीम थी 'एकल-उपयोग प्लास्टिक के स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल पेपर बैग के उपयोग को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता फैलाना।' कार्यक्रम का आयोजन 14 एमपी बटालियन एनसीसी, विदिशा के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अशुभान सिंह के मार्गदर्शन में तथा प्रभारी प्राचार्य डॉ. मलखान सिंह,



एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट (डॉ.) विनीता प्रजापति एनसीसी कैडेट्स एवं महाविद्यालय

स्टॉफ की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्लास्टिक को ना कहें और कागज को शानदार बनाएं' के संदेशों को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एनसीसी कैडेट्स द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने तथा पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर निर्माण, स्लोगन लेखन एवं 'बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट' प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कैडेट्स ने अनुपयोगी एवं पुनर्चक्रित सामग्री से पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम, वॉल हैंगिंग आदि आकर्षक एवं उपयोगी वस्तुएँ बनाकर अपनी रचनात्मकता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट (डॉ.) विनीता प्रजापति ने पर्यावरण संरक्षण विषय पर प्रेरणादायी व्याख्यान देते हुए विद्यार्थियों से दैनिक जीवन में सिंगल-यूज प्लास्टिक का प्रयोग छोड़कर पेपर बैग, कपड़े, जूट के बैग एवं अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्प अपनाने का आह्वान किया।

उन्होंने बताया कि छोटे-छोटे प्रयासों से भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देा जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय स्टॉफ एवं एनसीसी कैडेट्स ने प्लास्टिक मुक्त एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण हेतु अधिकाधिक पेपर बैग के उपयोग तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव कार्य करने की सामूहिक शपथ ली।

स्वच्छ भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालिक कार्ययोजना करें तैयार: मंत्री पटेल

कचरा संग्रहण, निष्पादन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बनाएं स्पष्ट नीति

भोपाल (नम्र)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की साधारण सभा की बैठक में कहा कि स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि सतत जनभागीदारी और सुव्यवस्थित प्रबंधन का विषय है। उन्होंने निर्देश दिए कि कचरा संग्रहण एवं निष्पादन के लिए स्पष्ट नीति तैयार की जाए तथा पंचायतों, ब्लॉक स्तर और वलस्टर स्तर पर दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण किया जाए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में ठोस एवं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए तथा अगले 20 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर कचरा नि्पादन प्रबंधन के उपाय करें। उन्होंने कचरा परिवहन के लिए वाहनों, एजेंसियों और संचालन व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित करने पर बल दिया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों को वलस्टर आधारित स्वच्छता व्यवस्था से जोड़ा जाए तथा इस्टर्बिन के प्रभावी उपयोग, वॉश ऑन व्हील्स मॉडल, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और गोबर–धन परियोजनाओं के प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने सीएसआर मद का उपयोग कचरा निष्पादन इकाइयों के विकास में करने, मल–कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन की प्रभावी व्यवस्था विकसित करने तथा खुले में कचरा डिपिंग की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि भूगतान व्यवस्था के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी तैयार की जाए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि एक अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किए जा चुके हैं तथा राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में कचरा प्रबंधन के लिए वर्कप्लो मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। वॉश ऑन व्हील्स अभियान के अंतर्गत 1,924 वलस्टरों में कार्य संचालित हैं तथा 9 हजार से अधिक पानी की टंकियों की सफाई की जा चुकी है। बैठक में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के वार्षिक लक्ष्यों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, गोबर–धन परियोजना तथा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में चलेगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान 15 से 30 जुलाई तक विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए किया जाएगा जागरूक

भोपाल (नम्र)। विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने और समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक चलेगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान के अंतर्गत समयबद्ध रूप से जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट यूाइड युवाओं को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश देंगे। अभियान की शुरुआत 15 जुलाई 2026 को होगी। जागरूकता रैली, ड्रा अवैयरनेस रन की गतिविधियाँ होंगी। इस दौरान स्थानीय मीडिया के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाएंगे तथा नशा मुक्ति से जुड़े पम्पलेट वितरित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को नशा मुक्त जीवन की शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों द्वारा नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता के लिए रील्स एवं शॉर्ट फिल्म निर्माण तथा उनका प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही नशा मुक्ति विषय पर विशेष व्याख्यान और डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन आयोजित होंगे। उच्च शिक्षण संस्थानों के आसपास तम्बाकू, सिगरेट या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं हो, इस संबंध में भी जागरूकता सुनिश्चित की जाएगी। चित्रकला, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन, रंगोली एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी नशा मुक्ति का संदेश देंगे। इन गतिविधियों में विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान का उद्देश्य युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाकर उन्हें स्वस्थ जीवनशैली के लिए प्रेरित करना और शिक्षण संस्थानों के माध्यम से नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहभागिता सुनिश्चित करना है।

दोस्ती या सियासी जुगलबंदी ?

राजनीति के अखाड़े में 'स्थायी दोस्त या दुश्मन' ढूँढना वैसा ही है, जैसे रेगिस्तान में पानी तलाशना। लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्गी-कैलाश की जुगलबंदी चर्चा का विषय बनी हुई है। दिग्विजय सिंह ने अयोध्या पदयात्रा की घोषणा की, तो कैलाश विजयवर्गीय का दिल पसीज गया। उन्होंने न केवल दिग्विजय को

ब्रिलियंटव इटेलीजेंट बताया, बल्कि 80 वर्ष की उम्र में उन्हें

युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी करार दे दिया। दिग्विजय ने भी कभी तपाक से कैलाश जी को कलाकार जी कहकर पलटवार किया था। दिग्विजय सिंह द्वारा कभी आरएसएस की तारीफ पर कैलाश का कायल होना यह आपसी सम्मान है या तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी का सियासी खेल? जनता सोच रही है कि ये राजनेता हैं या जुगलबंदी के मंझे हुए कलाकार!

दतिया में 'कटिंग' का साइड इफेक्ट

दतिया उपचुनाव के टिकट वितरण ने न केवल हलचल मचा दी है, बल्कि पार्टी के अंदरूनी समीकरणों की कलई भी खोल दी है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का पत्ता काटकर आशुतोष तिवारी का नाम आगे आना, पार्टी के मिशन अनुशासन का हिस्सा है या किसी नए पावर सेंटर को पनपने से रोकने का जतन? राजनीतिक पंडितों की मांनें तो यह सिर्फ जीतने की संभावना का सवाल नहीं था, बल्कि भाषा और व्यवहार की मर्यादा लांघने का दंड भी था। कहा जा रहा है कि पार्टी अलकामान उस अपशब्द संस्कृति से तंत आ चुका था। अब नामांकन के दिन पूर्व मंत्री जी का भावुक होना और घर-घर शीश नवाऊंगा का नारा देना, सहानुभूति बटोरने की आखिरी कोशिश है या वाकई प्रायश्चित? खैर, जनता तो कटिंग के बाद का स्वाद उपचुनाव के नतीजों में ही चखेगी।

राजधानी

ट्रैक्टर ने ऑटो को टक्कर मारी, 3 की मौत

सुरैना (नम्र)। सुरैना जिले के माता बसैया थाना क्षेत्र में पत्थर लोड ट्रैक्टर-ट्रॉली ने श्रद्धालुओं से भरे ऑटो रिकशा को टक्कर मार दी। हादसे में महिला और दो पुरुषों समेत तीन की मौके पर मौत हो गई। मरने वालों में ऑटो ड्राइवर भी शामिल है। ऑटो में कुल 8 लोग सवार थे। 5 लोग घायल हैं। तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के मुताबिक ये लोग बानमौर विजय पुरा से माता बसैया के पास स्थित भूमिया बाबा मंदिर दर्शन के लिए गए थे। लौटते समय पारासर की तेवरिया के पास हादसा हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए।

घटना की सूचना मिलते ही माता बसैया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया। माता बसैया थाना प्रभारी विवेक तोमर के अनुसार हादसा सुबह साढ़े 10 बजे हुआ। ड्राइवर को छेड़ ऑटो सवार सभी लोग आपस में रिश्तेदार हैं।

हादसे में इनकी मौत हुई

महेंद्र पुत्र बाबू लाल राठौर (50)
मनोरमा पत्नी राजेंद्र राठौर (45)
रामकेश पिता देवीराम कुशवाह
हादसे में 5 घायल, 3 गंभीर
सूरज पुत्र महेंद्र राठौर (24)

रायसेन में अनाज कारोबारी के घर 1 करोड़ की चोरी

● गुना से दबोचे गए अंतरराज्यीय गैंग के 2 शातिर, राजस्थान-गुजरात तक फैले तार

रायसेन (नम्र)। जिले में पुलिस ने बरेली कस्बे में एक अनाज कारोबारी के घर हुई करीब 1 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के जेवरों की सनसनीखेज चोरी के मामले में अंतरराज्यीय गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी गुना जिले के धानाओदा थाना क्षेत्र के खेजरा चक गांव से हुई है। यह वारदात बीती 5 जुलाई की रात को बरेली



कस्बे में रहने वाले अनाज व्यापारी राजेंद्र वर्मा के घर पर हुई थी। यह इलाका जिला मुख्यालय से करीब 88 किलोमीटर दूर है। वारदात के बाद से ही पुलिस की कई टीमों चोरों की तलाश में जुटी थीं। **टैक्निकल इनपुट और फॉरेंसिक सबूतों से मिला सुराग-** शिकायत दर्ज होने के बाद रायसेन पुलिस ने सायबर सेल, टैक्निकल इनपुट और घटनास्थल से मिले फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर जांच शुरू की। पुलिस को सटीक मुखबि़र से सूचना मिली कि आरोपी गुना जिले के एक गांव में छिपे हैं। इसके बाद पुलिस ने फौरन रेड मारकर दो संदिग्धों को दबोच लिया।

हालाँकि, पुलिस के हाथ अभी तक चोरी गए जेवर नहीं लगे हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस गिरेह का सगरना सारा माल समेटकर मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छपेपारी कर रही है।

पूछताछ में खुले बड़े राज- पकड़े गए आरोपियों ने कबूल किया है कि इस वारदात में

एक गैंग का हाथ है।

गैंग के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग



फोरलेन पर रविवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में रतलाम के बाल चिकित्सालय में पदस्थ डॉ. मनीष सिंह और उनके 80 वर्षीय ससुर शिवनारायण राजौरिया की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ, जब परिवार भोपाल से रतलाम लौट रहा था। पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग

के सदस्यों का

अंतरराज्यीय गैंग